नई दिल्ली
27 सितंबर, 2026 रविवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 178

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com

Email : timesofpedia@gmail.com

अभी संन्यास नहीं लेंगे रोनाल्डो, पुर्तगाल के लिए खेलते रहेंगे 07

सैटेलाइट तस्वीर में भारत में मौसम दो हिस्सों में बंटा दिखा

आधे में घने बादल तो आधा साफ

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अत्याधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसेट-3डीएस ने भारत के आसमान से एक अद्भुत दृश्य कैद किया है।

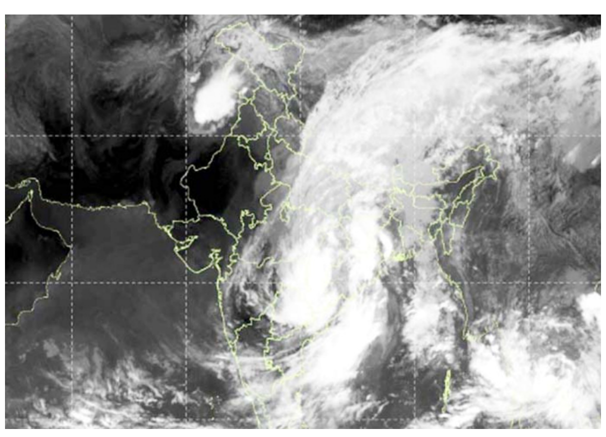

शुक्रवार को ली गई इस सैटेलाइट तस्वीर में भारतीय उपमहाद्वीप का मौसम साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटा नजर आया। देश का पूर्वी और दक्षिणी भाग जहां घने बादलों के आगोश में है, वहीं पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हिस्से में आसमान पूरी तरह साफ दिख रहा है। तस्वीर में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर वायुमंडलीय स्थितियों में एक अनोखा बंटवारा दिख रहा है। इसमें पूर्वी भारत, बंगाल की खाड़ी और आस-पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बादल बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10.83 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ वाले थर्मल इन्फ्रारेड चैनल का इस्तेमाल करके ली गई यह सैटेलाइट तस्वीर भारत और पड़ोसी देशों में बादलों के फैलाव को दिखाती है। इसकी सबसे खास बात बादलों का एक बड़ा और चमकदार समूह है जो बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत तक फैला है। इसके अलावा, दक्षिणी प्रायद्वीप और आस-पास के समुद्री इलाकों में भी बादलों की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। इसके उलट, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत का ज्यादातर हिस्सा बादलों से मुक्त दिख रहा है, जिससे इन दोनों इलाकों के बीच साफ तौर पर एक अंतर दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर उस समय की स्थिति दिखाती है जब दक्षिण-पश्चिम मॉनसून भारत के कुछ हिस्सों से लौटने की प्रक्रिया में है, जबकि वायुमंडलीय सिस्टम अलग-अलग इलाकों में बारिश पर असर डाल रहे हैं। पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बादलों के बनने का संबंध नमी वाली हवाओं, कम दबाव वाले सिस्टम और अन्य वायुमंडलीय हलचलों से हो सकता है।

देश के मौसम पर असर डालती हैं

इनसेट-3डीएस सैटेलाइट भारत के मौसम संबंधी सैटेलाइट प्रोग्राम का हिस्सा है और यह बादलों, वायुमंडलीय तापमान, नमी और मौसम से जुड़े अन्य पैमानों की जानकारी देता है। इसका थर्मल इन्फ्रारेड इंस्ट्रूमेंट पृथ्वी और वायुमंडल से निकलने वाले रेडिएशन का पता लगाता है, जिससे मौसम वैज्ञानिक रात में भी बादलों के पैटर्न को देख पाते हैं। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में बादलों की स्थिति में कितना बड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि अलग-अलग वायुमंडलीय स्थितियां देश के मौसम पर असर डालती हैं।

जयशंकर की लावरोव और अराघची से हुई मुलाकात

न्यूयॉर्क। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सत्र से इतर रूस और ईरान के अपने समकक्षों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और ब्रिक्स में सहयोग समेत विभिन्न मौजूदा मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और द्विपक्षीय संबंधों तथा ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। भारत ने इसी महीने ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।

बेल्जियम से आया 308 पहियों वाला ट्रक 4 राज्यों से गुजरेगा

नई दिल्ली। इन दिनों 308 पहियों वाला एक विशालकाय ट्रक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बेल्जियम से समुद्री रास्ते से लाई गई करीब 200 टन वजनी एक औद्योगिक मशीन को यह विशेष ट्रेलर उत्तर प्रदेश ले जा रहा है। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर उतारी गई इस मशीन को 308 पहियों वाले हाइड्रोलिक मॉड्यूलर ट्रेलर पर लोड किया गया, जिसका अंतिम गंतव्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के कुंभी स्थित बलरामपुर चीनी मिल की इकाई है। यह ट्रक ओडिशा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा।

इतने बड़े आकार और अत्यधिक वजन के कारण इस ट्रक का सफर सामान्य वाहनों जैसा नहीं है। इसकी औसत रफ्तार महज 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, और यह 24 घंटे में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाता है। अत्यधिक भार और सुरक्षा कारणों से इसे तेज गति से चलाना जोखिम भरा होता है। सड़क की भार क्षमता, तीव्र मोड़ लेने की क्षमता, वाहन की विशाल लंबाई-चौड़ाई और ऊपर से गुजरने वाले तारों की ऊंचाई जैसे कई तकनीकी पहलू इसकी धीमी गति के लिए जिम्मेदार हैं। रास्ते में आने वाली भौतिक और तकनीकी बाधाओं को हटाना पड़ रहा है। वाराणसी के मोहनसराय के पास कम ऊंचाई वाले फुट ओवरब्रिज के कारण ट्रक को कई दिनों तक रोका गया। वहीं बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से निकालने के लिए बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ी और कुछ समय के लिए रेल यातायात भी रोकना पड़ा।

फॉर्म-6 में किया बदलाव पूरी तरह अवैध चुनाव आयोग के पास संशोधन का अधिकार नहीं

रमेश बोले- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ज्ञानेश कुमार को जवाबदेह ठहराना चाहिए

नई दिल्ली। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े विवाद के बीच शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जवाबदेह ठहराना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को युवा मतदाताओं के लिए विशेष नामांकन शिविर आयोजित करने और सोशल मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया। रमेश ने आरोप लगाया कि फॉर्म-6 में किया गया बदलाव पूरी तरह अवैध है और निर्वाचन आयोग के पास इसमें एकतरफा संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि जुलाई, 2026 की शुरूआत में ऑनलाइन फॉर्म में बिना किसी आधिकारिक अधिसूचना के बदलाव किया गया और उसमें एक नया अनिवार्य खंड जोड़ा गया, जिसमें आवेदकों से यह जानकारी मांगी कि उनके माता-पिता या दादा-दादी पिछले एसआईआर में शामिल थे या नहीं। रमेश ने कहा कि यह प्रावधान खासकर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए बाधा पैदा करता है। उन्होंने दावा किया कि फॉर्म-6 में संशोधन करने की शक्ति निर्वाचन आयोग के बजाय केंद्र सरकार के पास है और ऐसा बदलाव संबंधित नियमों में संशोधन के बिना नहीं किया जा सकता।

जवाबदेही तय करनी चाहिए

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रमेश ने पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960 का हवाला देते हुए दावा किया कि फॉर्म में बदलाव के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन और संसद को इसकी सूचना दिया जाना जरूरी था। उन्होंने दावा किया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव को अवैध और अनधिकृतबताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी ताकि युवा और पहली बार मतदाता बनने वाले लोग बिना परेशानी के अपना पंजीकरण करा सकें। रमेश ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में संवैधानिक परंपराओं और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जवाबदेही तय करनी चाहिए।

संक्षिप्त वार्ता

मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक जीतने पर देश की पुरुष कबड्डी टीम को दी बधाई

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर देश की पुरुष कबड्डी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते फाइनल में ईरान को 40-34 से पराजित कर संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया है।

भोपाल के मास्टर प्लान का ड्रॉफ्ट जारी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि श्री गणेश अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर एक लंबे अंतराल के बाद भोपाल विकास योजना-2047 (मास्टर प्लान) के प्रारूप (ड्रॉफ्ट) का प्रकाशन कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा कि कैपिटल सिटी की यह विकास योजना (मास्टर प्लान) भोपाल की प्राकृतिक धरोहर- भोजताल, वन क्षेत्रों एवं बाघ भ्रमण क्षेत्र के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी और आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई है। इस विकास योजना में हरित टीडीआर का बेहतर प्रावधान किया गया है, इससे हरित क्षेत्र में आने वाली भूमि के स्वामियों की क्षतिपूर्ति के साथ विकासकताओं को टीडीआर के जरिए अतिरिक्त विकास की सुविधा भी मिल सकेगी।

जबलपुर में बरगी के 13 गेट खुलते ही तीसरी बार उफान पर नर्मदा

जबलपुर। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ने से शनिवार को बरगी बांध के 13 गेट खोल दिए गए। शनिवार को बांध के 13 गेट एक मीटर से अधिक ऊंचाई तक खोलकर नर्मदा में जलराशि की निकासी किए जाने के बाद तीसरी बार मां नर्मदा उफान पर आ गई। तीन से चार फीट तक जलस्तर बढ़ने से गौरीघाट के सभी घाट एक बार फिर डूबने की कगार पर पहुंच गए।

नागालैंड में जहरीली शराब का तांडव: 19 लोगों की मौत, जाँच जारी

नागालैंड। नागालैंड में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब ने कहर बरपा दिया है, इससे राज्य के मोकोकचुंग और तुएनसांग जिलों में करीब 19 लोगों की कथित तौर पर मौत हुई है। बीते दो दिनों में सामने आई इन दुखद घटनाओं ने प्रशासन को हिला दिया है। मोकोकचुंग में आठ और तुएनसांग में ग्यारह लोगों ने संदिग्ध अवैध शराब पीने के बाद मौत हो गई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नागालैंड में 1990 से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है, जो इस त्रासदी को गंभीर बनाती है।

इन मौतों के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखकर संदिग्ध मिलावटी शराब के स्रोत और उसकी पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व एडिशनल

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आई बुंगलांग चांग कर रहे हैं, जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेसुप्रा केजो की देखरेख में काम कर रही है। मौत की असली वजह और शराब की प्रकृति जानने के लिए, संदिग्ध शराब के सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए गुवाहाटी भेज दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन विस्तृत जानकारी का खुलासा करना अभी जल्दबाजी होगी।

पुलिस ने प्रभावित इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाए। इस कार्रवाई के तहत, अब तक 19 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और बाजार से करीब 3,000 बोतलें संदिग्ध शराब जब्त की हैं। जिला अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे बिना पहचान, बिना लेबल या संदिग्ध अवैध शराब का सेवन बिल्कुल न करें। साथ ही, सलाह दी गई है कि यदि किसी को शराब पीने के बाद चक्कर आना, धुंधला दिखना, सांस लेने में दिक्कत या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हों, तब तत्काल चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। यह घटना शराबबंदी वाले राज्य में अवैध शराब के फलते-फूलते कारोबार और उसके घातक परिणामों को दिखाती है।

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर: घाट और दुकानें जलमग्न, प्रशासन अलर्ट पर

चित्रकूट। उत्तरप्रदेश के चित्रकूट जिले में हो रही बारिश और मध्य प्रदेश से आ रहे पानी के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे प्रसिद्ध रामघाट के कई घाट, मंदिर और आसपास की दुकानें पूरी तरह जलमग्न हुई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, एहतियातन स्कूल-कॉलेज बंद किए गए हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। निवासियों के अनुसार, पिछले तीन-चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात बिगड़ रहे हैं।

वायुसेना को मिलेंगे 160 स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड हथियार

नई दिल्ली। भारत ने वायुसेना की लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन की खरीद के लिए करीब 811 करोड़ रुपये का करार किया है। यह समझौता भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया गया है। हथियारों की खरीद बाय इंडियन-इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड श्रेणी के तहत होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। यह एयर-टू-ग्राउंड प्रिसिजन ग्लाइड बम है, जिसे लड़ाकू विमान से लंबी दूरी से लक्ष्य पर दागा जा सकता है।

इसका उद्देश्य दुश्मन के एयरफील्ड और उससे जुड़े महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बनाना है। बता दें कि वेपन उस ब्रह्मोस से ज्यादा खतरनाक है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई एयरवेस ध्वस्त किए थे।

पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त करने वाले ब्रह्मोस से ज्यादा खतरनाक

इस हथियार की खासियत यह है कि इसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पारंपरिक तरीके से सीधे विमान के ऊपर से गिराने के बजाय ग्लाइड करते हुए लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। इससे लड़ाकू विमान को लक्ष्य के बेहद करीब जाने की जरूरत कम हो सकती है। लंबी दूरी से सटीक हमला करने की क्षमता वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय वायुसेना के जगुआर, हॉक और सु-30एमकेआई जैसे लड़ाकू विमानों से इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी तैनाती से वायुसेना को दुश्मन के महत्वपूर्ण एयरफील्ड और अन्य सैन्य ढांचे पर दूर से हमला करने की अतिरिक्त क्षमता मिलेगी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस सौदे में लगभग 60 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री होगी। हथियार प्रणाली के कई महत्वपूर्ण सब-सिस्टम का निर्माण देश में किया जाएगा। इससे घरेलू रक्षा उद्योग, स्वदेशी तकनीक और सैन्य उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हथियारों की आपूर्ति वित्त वर्ष 2027-28 और 2028-29 के दौरान किए जाने की योजना है।

बंगाल में 23 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर

कोलकाता पुलिस में भी फेरबदल, सुवेंदु सरकार की सर्जरी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी की है. एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 23 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसमें कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस में बड़ा फेरबदल करते हुए एक साथ 23 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों का तबादला किया है. राज्य के गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, फेरबदल के तहत कोलकाता पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि राज्य पुलिस के अधिकारियों को भी अलग-अलग पदों पर तैनात किया गया है.

कोलकाता को मिला नया ज्वाइंट सीपी-ट्रैफिक

राज्य पुलिस की आईबी में डीआईजी रहे भोलानाथ पांडे को कोलकाता पुलिस का नया संयुक्त आयुक्त (ट्रैफिक) नियुक्त किया गया है. इसी तरह, राज्य पुलिस में डीआईजी (सिक्योरिटी) के पद पर तैनात सुखेंदु हीरा को कोलकाता पुलिस का संयुक्त आयुक्त (सिक्योरिटी) बनाया गया है. पश्चिम बंगाल पुलिस क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (डब्ल्यूबीसीआरबी) की आईजी रहीं नीलू शेरपा को पश्चिम बंगाल पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डब्ल्यूबीपीएचआईडीसी) का आईजी नियुक्त किया गया है. वहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस होमगार्ड के पूर्व आईजी शंका शुभ्रा चक्रवर्ती को डब्ल्यूबीसीआरबी का नया आईजी बनाया गया है.

ताजा तबादलों के तहत कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेंद्र प्रकाश सिंह को उत्तर बंगाल में इंटेलिजेंस ब्रांच (आईबी) का महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त किया गया है. वहीं, कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त (ट्रैफिक) सूर्य प्रताप यादव को राज्य पुलिस की आईबी में उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) बनाया गया है. कोलकाता पुलिस के एनफोर्समेंट ब्रांच के उपायुक्त (डीसी) स्पर्शा नीलांगी को डिटेक्टिव डिपार्टमेंट (डीडी) का नया डीसी नियुक्त किया गया है. वहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के आईजी रहे सुधीर कुमार नीलकंठम को कोलकाता पुलिस का नया अतिरिक्त आयुक्त बनाया गया है.

बीरभूम को मिला नया एएसपी

डब्ल्यूबीपीएचआईडीसी के पूर्व डीआईजी देबर्षि दत्ता को विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है. पश्चिम बंगाल सशस्त्र पुलिस बल की 10वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर नीमा नरबू भूटिया को पश्चिम बंगाल पुलिस की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) में विशेष पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है.

डीएमके पर विजय का हमला: आलोचनाएं बेअसर, सवाल जारी रखूंगा

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख सी.जोसेफ विजय ने कहा है कि विपक्ष, खासकर द्रमुक की आलोचनाएं उन पर बेअसर हैं और वे द्रमुक के पुराने रिकॉर्ड पर लगातार सवाल उठता रहूंगा। यह बात उन्होंने मदुरांतकम विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार मरगतम कुमारवेल के प्रचार के दौरान कही।

विजय ने द्रमुक की रणनीति पर निशाना साधा, जिसमें उनकी आलोचनाओं को पुराना बताकर खारिज किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि द्रमुक मानती है कि युवा पीढ़ी 50 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामलों से अनजान है, जिससे वह अपनी बेदाग छवि बनाए रखने में सफल रही है। विजय ने कहा, जब वे पुराने मामले उठाते हैं,तब द्रमुक घटिया और मानहानिकारक हमले करती है। अपनी ह्यमोटी चमड़ीह्न का जिक्र कर विजय ने कहा कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने 30-35 साल तक बहुत कुछ देखा है, इसलिए ये हमले उनके लिए नए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे इससे भी ज्यादा की उम्मीद करते हैं।

भारत को कबड्डी में दो गोल्ड, महिला-पुरुष टीम चैंपियन

नागोया (जापान)। भारत ने शनिवार को एशियन गेम्स में कबड्डी के दोनों गोल्ड जीत लिए। महिला टीम ने ईरान को 37-34 और पुरुष टीम ने 40-34 से हराया। पुरुष टीम ने लगातार 10वीं और महिला टीम ने लगातार 5वीं बार मेडल जीता। एथलेटिक्स में तजिंदरपाल सिंह तूर और सावन बरवाल ने सिल्वर, जबकि प्राची चौधरी ने 400 मीटर में ब्रॉन्ज जीता। शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम ने सिल्वर हासिल किया। स्क्वॉश में अनाहत सिंह और अभय सिंह फाइनल में पहुंचे, जबकि पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची।

बिहार में चलती तीर्थयात्री बस में भीषण आग, बाल-बाल बचे 60 यात्री

एलएच-31 पर धू-धूकर जली नेपाल से गया जा रही बस

खगड़िया। बिहार के खगड़िया जिले में अहले सुबह एक बड़ा हादसा टल गया जब मानसी थाना क्षेत्र में एनएच-31 पर नेपाल से गया जा रही तीर्थयात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई। बस में सवार करीब 60 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना अनिल होटल के सामने एनएच-31 पर हुई। बस में सवार सभी यात्री गया में पिंडदान करने जा रहे थे। यात्रियों ने बताया कि पहले बस के एक टायर से धुआं निकलता दिखाई दिया, जो तेजी से बस के अंदर फैलने लगा। खतरे को भांपते हुए यात्रियों ने तुरंत बस से नीचे उतरना शुरू कर दिया। सभी के उतरने के कुछ ही देर बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। यात्रियों की त्वरित प्रतिक्रिया और सूझबूझ के कारण सभी लोग सुरक्षित बच गए। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगने का प्रारंभिक कारण टायर से निकला धुआं बताया जा रहा है।

संपादकीय

वोट को लेकर जन-आंदोलन

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय जन-आंदोलन का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने राज्यों की राजधानियों में विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक भी 29 सितंबर को तय हुई है। शायद कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा! राजनीतिक कॉकरोचों ने भी सीईसी का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन की धमकी दी है। विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने सीईसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और जेल में डालने की पुरजोर मांग की है। हालांकि दिसंबर, 2023 में चुनाव आयोग संबंधी कानून में संशोधन कर सीईसी, पूर्व सीईसी और चुनाव आयुक्तों को किसी भी तरह के केस और जेल भेजने की सजा से कानूनी छूट दी गई थी। उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह संशोधन संसद में पारित किया गया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेता इस संसदीय संशोधन को जानते होंगे! फिर भी नेता प्रतिपक्ष ने सीईसी को गद्दार और देशद्रोही करार दिया है। उनके इस्तीफे और सरकारी गवाह बनने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष को यकीन है कि ऐसे अपराधी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। विपक्ष का कथित इंडिया ब्लॉक संसद के दोनों सदनों में, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है। इसी साल मार्च-अप्रैल में भी महाभियोग का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति ने खारिज कर दिया था। लेकिन आसार पुख्ता होते जा रहे हैं कि शहर, कस्बा, गांव और गली-गली के स्तर पर देश का आम नागरिक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का ही बहिष्कार कर दे! चूंकि उनके वोट काटे जा रहे हैं, लिहाजा संविधान में दिए मताधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। यदि संविधान का ही उल्लंघन होता रहा, तो लोकतंत्र किस काम का..? लोकतंत्र की बुनियाद ही आम मतदाता का वोट और जनादेश है। यदि वोट से संसद, विधानसभा, सरकारें नहीं चुनी जा सकतीं, तो वोट ही बेमानी किया जा रहा है। जन-आंदोलन इस मताधिकार को हासिल करने और एसआईआर की आड़ में चुनावी साजिश को पराजित करने को लेकर उग्र और देशव्यापी होगा। अब यह लोकतंत्र-समर्थक लामबंदी की ही अग्नि-परीक्षा है कि वे आम नागरिक को कितना समझा पाते हैं कि वोट चोरी के जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं? राहुल गांधी और विपक्षी नेता अभी तक वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, लिहाजा उन्हें क्षुद्र राजनीति माना जा रहा था। अब चुनाव आयोग के ही दो संवैधानिक चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों और सवालों से लगभग पुष्टि हो रही है कि वोट चोरी ही नहीं, वोट देने का मौलिक अधिकार भी छीना जा रहा है। एक अभियान के तहत करीब 13.37 करोड़ मतदाताओं के नाम काट देना कोई सामान्य घटना नहीं है।

गोवा जैसे छोटे-से राज्य का उदाहरण सार्वजनिक हुआ है कि 97 मतदाताओं के नाम और ब्यौरे सही पाए गए, लेकिन राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी 8 बार ई-मेल कर और फोन पर ब्रीफ करने के बावजूद उन 97 नामों को मतदाता-सूची में जुड़वा नहीं सका। इसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। उन मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार छिन गए, वे वोट नहीं दे सकेंगे, ऐसे लोकतंत्र का क्या करेंगे हम? यह कैसी प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्य के सीईओ की भी आयोग के आईटी सिस्टम तक पहुंच नहीं है! यकीनन अब यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी तक भी जाएगा। मुद्दा यह नहीं है कि सीईसी के पद पर ज्ञानेश का चयन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की असहमति को किनारे कर दिया गया। सरकारें ऐसे ही काम करती हैं और चयन प्रधानमंत्री के स्तर पर ही होता रहा है। इसमें साजिश क्या है? चूंकि अब चुनाव आयोग का भीतरी यथार्थ बेनकाब हुआ है, किसी ने भी उसका खंडन नहीं किया है, किसी ने भी सफाई नहीं दी है या अदालत में उसे चुनौती दी है, अंततः सीईसी ज्ञानेश को ही खलनायक माना जा रहा है। यदि देश भर में जन-आंदोलन फैलता है, तो प्रधानमंत्री कब तक सीईसी को बचा पाएंगे? यह भाजपा-कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, देश के आम नागरिक के मताधिकार का सवाल है और यह राष्ट्रीय सरोकार का मुद्दा बन सकता है। विपक्ष का गंभीर आरोप है कि केंद्र तथा कई राज्यों में सरकार निर्माण में चुनाव आयोग की भूमिका पक्षपातपूर्ण रही है। अगर यहां पर निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते, तो निश्चय ही भाजपा की सरकारें न बनतीं। राहुल गांधी का मानना है कि इन जगहों पर दोबारा से निष्पक्ष चुनाव करवाए जाने चाहिएं। उनकी यह भी मांग है कि इस मसले को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकारी गवाह बनना चाहिए। कांग्रेस कई राज्यों में इस मसले को लेकर आंदोलन शुरू करने जा रही है। शायद केंद्र पर कुछ दबाव बने।

मोबाइल की दीवानगी कहां लेकर जाएगी?

व्यापक संदर्भ में देखें, तो ऐसे मामलों में दोष केवल युवाओं का भी नहीं है। कुछ बच्चे माता-पिता पर दबाव बनाते हैं कि अगर उन्हें लेटेस्ट फोन नहीं मिला तो वे पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चे महंगा स्मार्टफोन यह कहकर मांगते हैं कि इससे पढ़ाई, प्रोजेक्ट और नई तकनीक सीखने में मदद मिलेगी। खासकर कम पढ़े-लिखे माता-पिता को बच्चे कई बार इन वजहों का हवाला देकर समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई मामलों में असली वजह दोस्तों के बीच फोन को प्रदर्शित करना और खुद को उनसे पीछे न दिखाना होती है। भारत में मार्केट रिसर्च फर्म ह्यकाउंटरपॉइंट रिसर्चह्ल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल बिकने वाले कम से कम 42 प्रतिशत आईफोन ईएमआई (किस्तों) पर खरीदे जाएंगे। देश के ज्यादातर परिवारों की आय सीमित है। ऐसे में 75000 रुपए या उससे महंगे फोन की किस्तें चुकाना कई परिवारों को कर्ज में धकेल रहा है।

युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। देश का भविष्य बनने वाले युवा भविष्य की चिंता किए बगैर सिर्फ एक झूठी होड़ का शिकार हों तो देश का भला कैसे होगा? मौजूदा दौर में मोबाइल को लेकर जो मारामारी मची हुई है, उसे देख कर लगता है कि जैसे देश के युवाओं के सामने कोई चुनौती नहीं बची है। युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य पर मोबाइल के नए से नए ब्रांडों का आकर्षण उन्हें दलदल की तरफ धकेल रहा है। महंगे मोबाइल ब्रांडों के जुनून से तो यही लगता है कि इस देश में बेरोजगारी और युवाओं से जुड़ी कोई समस्या बची ही नहीं है। नए से नए मोबाइल ब्रांड को पाने के लिए देश के युवा मारामारी करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे इतने जरूरी काम में जुटे हुए हैं कि यदि यह नहीं हुआ तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। एक अमरीकी कंपनी के नए ब्रांड को लेकर युवा रातभर लाइन में खड़े रहे और अपने नंबर का इंतजार करते रहे। दिल्ली से मुंबई तक देश के कई शहरों में इस कंपनी के स्टोर के बाहर सैकड़ों लोग सुबह स्टोर खुलने की इंतजार में रात भर कतार में लगे रहे। वह भी एक ऐसे मोबाइल के लिए जिसकी कीमत भी डेढ़ से सवा तीन लाख रुपए तक की है। इनमें चंद ही ऐसे युवा होंगे जो इतने महंगे फोन से कुछ कमाई करेंगे, बाकी सभी तो सिर्फ जुनून के शिकार हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लोग महंगा फोन खरीदने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं?

बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोगों को नया फोन, नई कार, नया गैजेट या कोई भी लेटेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले खरीदने की इतनी जल्दी क्यों होती है। साइकोलॉजी में इसे नयापन अर्थात अनोखा या अलग अनुभव करने की इच्छा कहते हैं। इसे आकर्षण से जोडकर देखा जाता है। इनसान को नई और अलग चीजें स्वाभाविक तौर पर दिलचस्प लगती हैं। नए प्रोडक्ट के साथ नई तकनीक, नया डिजाइन और नई पहचान जुड़ी होती है। नवीनतम फोन खरीदने की इस होड़ के पीछे फोमो यानी दूसरों से पीछे छूट जाने का डर भी हो सकता है। लोगों को लगने लगता है कि बाकी सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और अगर उन्होंने यह फोन नहीं लिया तो वे पीछे रह जाएंगे। यही कारण है कि कुछ लोग नया फोन आने का महीनों इंतजार करते हैं और लॉन्च होते ही उसे खरीदने के लिए घंटों लाइन में लग जाते हैं। कुछ लोग हर चीज सबसे पहले क्यों लेना चाहते हैं? हर व्यक्ति नई चीज के पीछे एक ही वजह से नहीं भागता। किसी को नई तकनीक पसंद होती है, किसी को नई चीज इस्तेमाल करने का अनुभव अच्छा लगता है, जबकि कुछ लोगों के लिए सबसे पहले नया प्रोडक्ट खरीदना उनकी पहचान और सोशल स्टेटस से जुड़ जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नया फोन दिखाकर रील बनाने और उसे प्रदर्शित करने की चाहत भी इसके आकर्षण को बढ़ा सकती है। कई युवा लेटेस्ट फोन खरीदने के लिए ईएमआई का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अभी फोन ले लेते हैं और पैसे धीरे-धीरे चुका देंगे। सोशल मीडिया ने इस सामाजिक दबाव को और बढ़ाया है। इसका असर सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं में भी लेटेस्ट प्रोडक्ट को लेकर ऐसा क्रेज देखने को मिलता है। कई मामलों में माता-पिता बच्चों की इस जिद से परेशान होकर काउंसिलिंग के लिए पहुंचते हैं। मोबाइल फोन की चाहत को लेकर देश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक युवक ईएमआई पर खरीदे गए एप्पल आईफोन की मासिक किस्त के पैसों को लेकर हुए झगड़े के बाद तिसगांव की एक पहाड़ी पर चढकर कूदने की धमकी दे रहा था। वह नीचे गिर पड़ा। उसे बचाने और नीचे उतारने की कोशिश में उसके पिता भी संतुलन बिगड़ने से उसके साथ 250 फुट गहरी खाई में गिर गए और आंखों के सामने पूरे परिवार को उजड़ता देख सदमे में आई मां ने भी चट्टान से छलांग लगा दी। मोबाइल ने तीनों की जान ले ली। इसी तरह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 फरवरी 2026 को तीन सगी नाबालिग बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। माता-पिता द्वारा ऑनलाइन गेमिंग और अत्यधिक मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाने व फोन छीन लिए जाने के बाद उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया। अगस्त 2026 को यूपी के फरूर्खाबाद में 25 वर्षीय युवती ने पिता द्वारा उसका मोबाइल फोन छीनने पर आत्महत्या कर ली। हिमाचल प्रदेश में मार्च 2025 में मंडी में एक बेटी ने पढ़ाई या परीक्षा के दौरान पिता द्वारा मोबाइल फोन छीन लिए जाने से आहत होकर आधी रात को विक्टोरिया पुल से ब्यास नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। आगरा में एक पिता के मोबाइल तोड़ने पर 17 वर्षीय बेटी ने फांसी लगा ली थी। दिसंबर 2023 में नागपुर में एक 16 वर्षीय किशोरी ने फोन का इस्तेमाल रोकने पर आत्महत्या कर ली। दरअसल, ऐसी घटनाओं के पीछे उपभोक्तावाद, दिखावे की संस्कृति, साथियों के दबाव, डिजिटल दुनिया में निर्मित कृत्रिम जीवन शैली और तत्काल अपनी इच्छा पूरी कर लेने की बढ़ती प्रवृत्ति जैसे कई पहलू हो सकते हैं। व्यापक संदर्भ में देखें, तो ऐसे मामलों में दोष केवल युवाओं का भी नहीं है। कुछ बच्चे माता-पिता पर दबाव बनाते हैं कि अगर उन्हें लेटेस्ट फोन नहीं मिला तो वे पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चे महंगा स्मार्टफोन यह कहकर मांगते हैं कि इससे पढ़ाई, प्रोजेक्ट और नई तकनीक सीखने में मदद मिलेगी। खासकर कम पढ़े-लिखे माता-पिता को बच्चे कई बार इन वजहों का हवाला देकर समझाने की कोशिश करते हैं।

हालांकि कई मामलों में असली वजह दोस्तों के बीच फोन को प्रदर्शित करना और खुद को उनसे पीछे न दिखाना होती है। भारत में मार्केट रिसर्च फर्म ह्यकाउंटरपॉइंट रिसर्चह्ल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल बिकने वाले कम से कम 42 प्रतिशत आईफोन ईएमआई (किस्तों) पर खरीदे जाएंगे। देश के ज्यादातर परिवारों की मासिक आय बहुत सीमित है। ऐसे में 75000 रुपए या उससे महंगे फोन की किस्तें चुकाना कई परिवारों को कर्ज के दलदल में धकेल रहा है। भारत में 5 करोड़ से भी कम ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 75000 रुपए है। वहीं, एक आईफोन की औसत कीमत भी लगभग 75000 रुपए है। मतलब एक फोन की कीमत पूरे परिवार की महीने भर की कमाई से भी ज्यादा है। अभिभावकों और समाज को भी यह समझना होगा कि बच्चों को महंगी वस्तुएं उपलब्ध कराना और उन्हें जीवन के मूल्य समझाना दो अलग-अलग बातें हैं। बच्चों की हर मांग पूरी करके उन्हें खुश रखना आसान है, लेकिन उन्हें ह्यनहींह्ल सुनने की क्षमता देना निश्चित ही कहीं अधिक जरूरी है।

योगेंद्र योगी
स्वतंत्र लेखक

सरकार, चुनाव आयोग और न्याय पालिका में भगदड़?

देश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है, उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। चुनाव आयोग को लेकर एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं। अब इन सवालों की आंच केवल आयोग तक सीमित नहीं रह गई है। सरकार, चुनाव आयोग और न्याय पालिका की भूमिका सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गई है। सवाल यह नहीं है, आरोप किस पर लगे हैं। सवाल यह है, संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कैसे बचेगा?

सबसे बड़ा विवाद एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर है। पश्चिम बंगाल में लाखों नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। बड़ी संख्या में अपील, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए ट्रिब्यूनल बनाना, उनमें से बहुत कम मामलों का अब तक निपटारा, यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। हालिया आंकड़ों के अनुसार 38 लाख से अधिक अपीलें सामने आईं। बड़ी संख्या अभी भी लंबित है। जिन मामलों में फैसला आया है, उसमें 91 फीसदी मतदाता सही पाए गए हैं। अभी तक 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। 2024 के बाद से 18 साल की उम्र पूरी कर चुके मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ह्यलॉजिकल डिस्क्रेपेंसीह्ल के आधार पर जारी नोटिसों की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है क्या नोटिस यांत्रिक तरीके से भेजे गए हैं?

यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या मतदाता सूची केवल प्रशासनिक दस्तावेज है। या लोकतंत्र की बुनियाद है। यदि एक पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटता है। तो नुकसान केवल एक व्यक्ति का नहीं, उसके लोकतांत्रिक अधिकार का होता है। चुनाव आयोग ने जो नया पोर्टल बनाया है उसमें बीएलओ, एआर ओ, तथा जिला स्तर पर जो अधिकार मतदाता सूची को तैयार करने और मतगणना, चुनाव परिणाम घोषित करने के अधिकारों को चुनाव आयोग ने अपने पास ले लिया था। यह केंद्रीकृत व्यवस्था संवैधानिक नियमों के खिलाफ थी। इस पर सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। इसकी जानकारी दोनों चुनाव आयुक्त को भी नहीं दी गई। चुनाव आयोग के भीतर के मतभेद अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले महीनों में आयोग के कई निर्णयों पर आपत्तियां दर्ज कीं। अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच 14 आपत्तियों का उल्लेख सामने आया है। तीन सदस्यीय संवैधानिक संस्था में निर्णयों को लेकर ऐसी गंभीर असहमति है, तो देश को यह जानने का अधिकार है, निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया क्या थी। किस स्तर पर किसकी सहमति से निर्णय लिए गए। इसके साथ चुनाव आयोग के तकनीकी ढांचे, पोर्टल और सॉफ्टवेयर को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आयोग स्वयं अनेक डिजिटल एप्लीकेशन और पोर्टल संचालित कर रहा है। इसकी जानकारी भी दो चुनाव आयक्तों के पास नहीं है। नए तकनीकी बदलावों, डेटा प्रबंधन और मतदाता सूची से जुड़े सॉफ्टवेयर पर आयोग के भीतर ही पारदर्शिता को लेकर सवाल हैं। उनका सार्वजनिक और स्वतंत्र ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू न्यायपालिका है। एसआईआर को लेकर लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब अदालत स्वयं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल पूछ रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायपालिका पर आरोप स्वतः सिद्ध हो गए। यह जरूर है, न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठने वाले हर सवाल का जवाब न्यायपालिका द्वारा रिकॉर्ड पर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निजी संबंधों को लेकर भी तरह-तरह की जानकारी सार्वजनिक हो रही है। इसका भी खुलासा होना जरूरी है। नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम से जुड़ा मामला इस बहस को और संवेदनशील बनाता है। मेधा रूपम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पुत्री हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छात्रा की एनएसए हिरासत को रद्द करते हुए अधिकारियों पर गंभीर टिप्पणियां की थीं। 5 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट की टिप्पणियों और मुआवजा वसूली वाले हिस्से पर रोक लगा दी है। छात्रा की हिरासत रद्द करने का आदेश बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग फीड म्यूट किए जाने और मामले की लिस्टिंग को बदलने को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पारदर्शिता के साथ काम करना होगा, जो कानूनी संरक्षण मिला हुआ है वह निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करने के लिए मिला हुआ है। किसी संस्था को पहले से दोषी घोषित करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, चुनाव आयोग के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों, मतदाता सूची के डेटा, सॉफ्टवेयर मे हुये बदलावों और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का स्वतंत्र तकनीकी तथा न्यायिक ऑडिट हो। यदि सब कुछ सही है, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को जांच से कैसा डर? यदि कहीं गड़बड़ी है, तो उसे छिपाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। विपक्ष इन घटनाओं को सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा हथियार बना रहा है। राहुल गांधी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देकर पूरे मामले में गवाह बनने की मांग इसी राजनीतिक दबाव का हिस्सा है। लोकतंत्र में अंतिम फैसला आरोपों से नहीं, सबूतों और स्वतंत्र जांच से होना चाहिए। जब तक जांच पूरी नहीं होती, ऐसी स्थिति में ज्ञानेश कुमार को स्वयं अलग हो जाना चाहिए। सबसे खतरनाक स्थिति वह होगी जब सरकार चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग अधिकारियों पर और अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगें। यही वह बिंदु है, जहां व्यवस्था में भरोसे का संकट पैदा होता है। नाव डूब रही हो, तो सबसे पहले कौन भागा, यह इतिहास दर्ज करता है। लोकतंत्र की नाव को बचाने के लिए जरूरी है, कोई भागने नहीं पाए, सच सामने आए, जिम्मेदारी तय हो और संवैधानिक संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह रहें। चुनाव किसी सरकार का नहीं, जनता के विश्वास का परिणाम होता है। जिस दिन जनता को मतपत्र, मतदाता सूची चुनाव परिणाम और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहेगा, उस दिन लोकतंत्र का सबसे मजबूत किला भी ढह जाएगा। जिस तरह के खुलासे हुए हैं। उसके बाद चुनाव आयोग की निष्पक्षता चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चुनाव आयोग पर सरकार का दबाव यह सब मामला स्पष्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में अब यह मामला दबाना सरकार के बस की बात नहीं रही। न्याय पालिका की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गई है।

लेखक-सनत जैन

छात्रों की आत्महत्या के असल जिम्मेदार कौन?

> **आईआईटी मुंबई में एक छात्र की आत्महत्या ने फिर से कई पुराने सवाल खड़े कर दिये हैं लेकिन हम हैं कि असल मुद्दे छोड़कर लेकर पीटने में मशगूल हैं। जैसे नीट पेपर लीक में मंत्री के इस्तीफे को सारी समस्या का इलाज समझ लिया गया था वैसे ही इस प्रकरण में प्रोफेसर के इस्तीफे की मॉंग की जा रही है। एससी/एसटी एक्ट के अतार्किक लेकिन डरावने प्रावधानों के तहत प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गयी है। समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और सोशल मीडिया भी अच्छी बुरी प्रतिक्रियाओं से सराबोर है।**

गम्भीर सामाजिक समस्या को राजनीतिक रंग देकर भीड़तंत्र के हवाले कर देना आज के दौर में एक परम्परा हो गया है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम बार बार असल समस्या को नजरअंदाज करके शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छिपाये हुये हैं।

ऑन परपज नाम का पॉडकास्ट चलाने वाले विश्वप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर जय शेट्टी अपनी बेस्टसेलर किताब थिंक लाइक अ मॉन्क में लिखते हैं कि आम तौर पर बच्चों को दो तरह के झूठ सुनना पड़ता है। या तो यह कि; तुम जीवन में कुछ नहीं बन सकते या फिर यह कि; तुम जीवन में जो चाहो बन सकते हो। जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी वह नहीं बन सकता जो वो चाहता है लेकिन वह जरूर बन सकता है जो वो है। ये झूठ भारतीय समाज के अधिकांश परिवारों पर पूरी तरह फिट बैठते हैं और अक्सर बच्चों से उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है। उपभोक्तावाद से ग्रस्त समाज में यह समझा जाता है कि महंगी कोचिंग के दम पर बच्चा जो चाहे वह बन सकता है। इस त्रासदी का एक दुखद पहलू यह भी है कि विरले मातापिता ही बच्चों को नैतिकता, नागरिक जिम्मेदारी, समाजसेवा, देशप्रेम तथा परोपकार की शिक्षा देते हैं। अधिकांश मातापिता की महत्वाकांक्षा बच्चे के आईआईटी अथवा मेडीकल कॉलेज में दाखिले की होती है क्योंकि इन दो व्यवसायों से प्रतिष्ठा और पैसा दोनों ही हासिल होते हैं।

भारतीय सिस्टम में करियर चुनाव के लिये कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है इसलिये अक्सर मातापिता की महत्वाकांक्षा और समाज की तत्कालीन अपेक्षा ही करियर निर्धारित करती है। जबकि वास्तव में किसी भी बच्चे का करियर तीन बुनियादी प्रश्नों से तय किया जाना चाहिये। पहला; वह क्या बनना चाहता है, दूसरा; वह क्या बन सकता है और तीसरा; वह क्या बनने के काबिल है? चूंकि हमारे समाज बच्चों में मौलिक सोच विकसित होने की गुंजाइश कम होती है इसलिए वह आसानी से बाहरी दुनिया से प्रभावित हो जाता है। नतीजा यह कि अक्सर पहले प्रश्न के पीछे साथियों का सोच और तत्कालीन सामाजिक धारा का प्रभाव होता है और दूसरे प्रश्न के पीछे माता पिता की महत्वाकांक्षा। तीसरे प्रश्न का उत्तर किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व की बनावट और उसकी बौद्धिक क्षमता में मौजूद होता है लेकिन इन दोनों का सही आकलन न होने से सामाजिक दबाव और माता पिता की महत्वाकांक्षा ही ज्यादा असरदार साबित होते हैं। इसीलिये अधिकांश मातापिता द्वारा बच्चों को उनकी इच्छा के विपरीत और क्षमता के बाहर की पढ़ाई करने का दबाव डाला जाता है। और यह समस्या तब और भी गम्भीर हो जाती है जब बच्चों को महंगी कोचिंग क्लास में भेजा जाता है। पहले दसवीं कक्षा के बाद कोचिंग का फैशन था लेकिन भीषण प्रतिस्पर्धा के चलते अब कई कोचिंग संस्थान आठवीं कक्षा के बाद ही नीट या जेईई की तैयारी शुरू करवा देते हैं। इस कोचिंग कोर्स का लाखों खर्च के कारण मातापिता बच्चों को बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें हर हाल में सफल होना है। मातापिता भले ही इसे प्रेरणा समझें लेकिन यह बच्चों को और अधिक तनाव में डाल देता है। कोचिंग क्लास की कठिन दिनचर्या कुछ इस तरह है कि छात्र को परम्परागत स्कूल छोड़ना पड़ता है और उनका प्रवेश ऐसे डमी स्कूलों में करवा दिया जाता है जहां सिर्फ उनकी हाजिरी दिखाई जाती है। चूंकि छात्र स्कूल के वातावरण से वंचित रहते हैं इसलिये उन्हें किशोरावस्था में सामंजस्य, समझौता, सहयोग, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सीखने का अवसर ही नहीं मिलता। इसके बजाय वे कोचिंग के तनावपूर्ण माहौल में एक दूसरे से आगे निकलने के हुनर सीखते रहते है। इससे छात्रों का मानसिक और भावनात्मक विकास नहीं हो पाता और भावी जीवन में किसी भी कठिनाई और असफलता से छात्र टूट जाते हैं और कमजोर क्षणों में आत्मघात जैसे कठोर कदम भी उठा लेते हैं।

उपभोक्तावाद से प्रेरित समाज की सोच मातापिता की महत्वाकांक्षा तक पहुँच कर रुक गयी है। इसी का नतीजा है कि देश भर के नामी इंजीनियरिंग और मेडीकल संस्थानों में दाखिले के बावजूद बच्चे दबाव और तनाव में रहते हैं। कोचिंग के गलाकाट प्रतिस्पर्धा भरे माहौल में सालों साल कोशिश करते रहने के परिणामस्वरूप ऐसे कई छात्रों की मानसिक स्थिति बेहद नाजुक और कमजोर हो जाती है और नामी संस्थानों में पढ़ाई का दबाव उन्हें निराशा और अवसाद में धकेल देता है। नतीजा यह कि आत्महत्या की घटनाएं निरन्तर जारी हैं। लेकिन हम हैं कि समस्या को अजीबोगरीब रंग देकर अगली दुर्घटना का इंतजार करने लगते हैं। इस लीपापोती के मूल में यह भय है कि असलियत सामने आते ही उसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। और असलियत यही है कि इन आत्महत्याओं के वास्तविक जिम्मेदार महत्वाकांक्षी मातापिता और दिग्भ्रमित समाज हैं। हर आत्महत्या पर किसी को बलि का बकरा बना देने से आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। शिक्षाशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और योजनाकारों को पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा तब हम आत्महत्याएं रोक पायेंगे।

(लेखक- डॉ योगेन्द्र श्रीवास्तव)

आलेख

बीज की मुट्ठी में किसान का भविष्य

बीज की मुट्ठी में केवल अगली फसल नहीं, किसान का अगला मौसम भी बंद होता है। अब इसी बीज के बाजार में भारत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। वैश्विक बीज व्यापार में भारत की हिस्सेदारी करीब एक प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक दस प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। कारोबार को दस गुना बढ़ाने की यह महत्वाकांक्षा अपने आप में बड़ी है। मगर इसके साथ एक बुनियादी सवाल भी खड़ा होता है—बीज का बाजार दस गुना होगा तो किसान के अधिकार कितने मजबूत होंगे?

नई दिल्ली में 24 सितंबर को फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के दसवें वार्षिक आमसभा और ह्यएफएसआईआई नॉलेज डे 2026ह्ल में भारत के बीज उद्योग ने अपनी भविष्य की दिशा सामने रखी। उद्योग का अनुमान है कि देश का बीज कारोबार फिलहाल करीब 3.6 अरब डॉलर का है और 2030 तक पांच अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। उद्योग ने एक समान राष्ट्रीय बीज नियामकीय ढांचे, समयबद्ध मंजूरी और बौद्धिक संपदा अधिकारों को मजबूत करने की मांग रखी है।

एफएसआईआई के अध्यक्ष और सवाना सीड्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय राणा ने कहा कि भारत के पास विज्ञान, प्रतिभा और किसान—तीनों की ताकत है। उन्होंने तिलहन और दलहन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई और एक लाख करोड़ रुपये की अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना तथा उच्च उपज वाले बीजों से जुड़े राष्ट्रीय मिशन को महत्वपूर्ण पहल बताया। उद्योग का कहना है कि वह अनुसंधान में अपना निवेश बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए नियामकीय स्पष्टता, पूर्वानुमेय प्रक्रिया और नई किस्मों, गुणों तथा तकनीकों को तेज और विज्ञान-आधारित मंजूरी जरूरी है।

इस तर्क का आर्थिक आधार समझना कठिन नहीं है। बीज खेती की कुल लागत का लगभग 5 से 7 प्रतिशत होता है, लेकिन बेहतर बीज संभावित उत्पादकता में 30 से 40 प्रतिशत तक का लाभ दे सकता है। मगर यहां एक जरूरी फर्क है—उत्पादकता बढ़ना और किसान की आमदनी बढ़ना एक ही बात नहीं है।

अच्छा बीज तभी किसान के लिए अच्छा परिणाम देगा, जब उसके साथ पानी, मिट्टी, मौसम, खाद, बाजार और उचित कीमत की स्थितियां भी अनुकूल हों। सूखे या बेमौसम बारिश में फसल चौपट हो सकती है। उत्पादन बढ़ने के बाद बाजार भाव गिर जाए तो किसान की आय नहीं बढ़ती। महंगे बीज के साथ महंगी खाद और कीटनाशक की जरूरत बढ़े तो लागत का दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए बीज नीति को केवल नवाचार और व्यापार की नीति मानना अधूरा होगा। उसे किसान के जोखिम को कम करने वाली नीति भी होना चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आनुवंशिकी विभाग के पूर्व निदेशक और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के सचिव डॉ. ए.के. सिंह ने सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग की जरूरत बताई है। उनका जोर नई किस्मों, संकरों और तकनीकों को किसानों तक तेजी से पहुंचाने पर है, खासकर तिलहन और दलहन में, जहां उत्पादकता कम है और जलवायु का दबाव बढ़ रहा है। यहां प्राथमिकता का सवाल भी महत्वपूर्ण है। अनुसंधान का उद्देश्य केवल ऐसी किस्में विकसित करना नहीं होना चाहिए जिनका बाजार बड़ा हो। उन किस्मों की भी जरूरत है जो कम पानी में बेहतर प्रदर्शन करें, सूखे और अत्यधिक वर्षा को सह सकें, स्थानीय मिट्टी के अनुकूल हों और छोटे किसानों की परिस्थितियों में टिक सकें। जलवायु परिवर्तन के दौर में किसान को केवल अधिक उपज देने वाला बीज नहीं, अनिश्चित मौसम में कम जोखिम वाला बीज चाहिए। प्रगतिशील कृषि मंच के राष्ट्रीय संयोजक और नेशनल फार्मर्स एम्पावरमेंट इनिशिएटिव के संयोजक किशोर जायसवाल ने एक महत्वपूर्ण बात कही—किसान बेहतर बीज तब अपनाता है जब उसे खेत में उसका परिणाम दिखाई देता है। किसान नई तकनीक से भागता नहीं है; वह अपने जोखिम का हिसाब लगाता है। उसकी मांग है कि जिस समय दूसरे देशों के किसानों को नई बीज तकनीक मिलती है, उसी समय भारतीय किसान को भी उसका अवसर मिले। लेकिन नई तकनीक तक पहुंच और उसके प्रभाव की विश्वसनीय जानकारी दो अलग बातें हैं। किसी नई किस्म या तकनीक को बड़े पैमाने पर बाजार में पहुंचाने से पहले स्वतंत्र, बहु-क्षेत्रीय और खेत-स्तरीय परीक्षण जरूरी हैं। अलग-अलग मिट्टी, जलवायु और खेती की परिस्थितियों में उसके परिणाम सामने आने चाहिए। परीक्षण के निष्कर्ष सार्वजनिक हों और किसान को उसकी भाषा में यह बताया जाए कि बीज किस परिस्थिति में कितना लाभ दे सकता है और उसकी सीमाएं क्या हैं।

एक समान राष्ट्रीय नियामकीय ढांचा बनाना है तो उसमें किसान प्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों, राज्यों और सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी भी होनी चाहिए। ह्यएक देश, एक ढांचाह्ल का अर्थ केवल उद्योग के लिए एक खिड़की नहीं, बल्कि किसान के लिए भी स्पष्ट जवाबदेही होना चाहिए। यदि किसी बीज की गुणवत्ता पर सवाल उठता है तो किसान की शिकायत सुनने और उसका समाधान करने की व्यवस्था कितनी तेज होगी? फसल खराब होने की स्थिति में जिम्मेदारी कैसे तय होगी? मुआवजे का रास्ता क्या होगा? इन सवालों का जवाब भी नियामकीय ढांचे में होना चाहिए।

बौद्धिक संपदा अधिकारों का सवाल भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। नई किस्म विकसित करने वाले शोधकर्ता और कंपनियां अपने निवेश की सुरक्षा चाहती हैं। यह स्वाभाविक है। लेकिन कृषि में बीज केवल एक औद्योगिक उत्पाद नहीं है। किसान पीढ़ियों से बीज को बचाता, चुनता और आगे बढ़ाता आया है। इसलिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और किसान के पारंपरिक अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी है। किसान को केवल बीज का खरीदार मानने से कृषि का पूरा इतिहास गायब हो जाता है। स्थानीय किस्मों और पारंपरिक ज्ञान ने भारतीय कृषि को लंबे समय तक विविधता दी है। आज जब जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का संकट सामने है, तब स्थानीय बीजों का संरक्षण भी कृषि नीति का हिस्सा होना चाहिए। आधुनिक अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान को आमने-सामने खड़ा करने के बजाय उनके बीच संवाद बनाया जाना चाहिए। एफएसआईआई के आयोजन में नीदरलैंड के प्रतिनिधि ने भी भारत और नीदरलैंड के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं की बात रखी। बीज कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ज्ञान और तकनीक का आदान-प्रदान बढ़ सकता है। आयोजन में एफएसआईआई के महानिदेशक डॉ. परेश वर्मा, सथगुरु मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. के. विजयराघवन और बायरेक के जीजीएम एवं अनुसंधान विकास प्रमुख डॉ. मनीष दीवान सहित अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। भारत को वैश्विक बीज व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है तो अनुसंधान और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। लेकिन इस दौड़ में यह नहीं भूलना चाहिए कि वैश्विक बाजार का विस्तार और भारतीय किसान का हित हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। कोई बीज कंपनी के लिए सफल उत्पाद हो सकता है, लेकिन किसी खास क्षेत्र के छोटे किसान के लिए महंगा या अनुपयुक्त भी हो सकता है। इसलिए नीति का केंद्र केवल बाजार नहीं, किसान की उपयोगिता और सुरक्षा होनी चाहिए। 2035 के लक्ष्य की सफलता को केवल निर्यात और बाजार हिस्सेदारी से क्यों मापा जाए? यह भी देखा जाना चाहिए कि प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीज छोटे किसानों तक कितनी आसानी से पहुंचा, नई किस्मों की जानकारी कितने किसानों तक पहुंची, खराब बीज की शिकायतों का समाधान कितने समय में हुआ, क्षति की स्थिति में किसान को कितनी राहत मिली और सार्वजनिक अनुसंधान में कितना निवेश बढ़ा। स्थानीय बीज विविधता के संरक्षण और नई तकनीक तक समान पहुंच भी इस सफलता के पैमाने होने चाहिए।

भारत का बीज उद्योग बड़ा हो, भारतीय कंपनियां दुनिया में जाएं और देश वैश्विक बीज केंद्र बने—इसमें कोई समस्या नहीं। सवाल यह है कि इस विस्तार का लाभ किस तरह बांटा जाएगा। यदि अनुसंधान का लाभ किसान तक तेजी से पहुंचे, बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित हो, जोखिम की जिम्मेदारी केवल किसान पर न डाली जाए और उसे विकल्पों की जानकारी मिले, तभी यह विस्तार कृषि के लिए व्यापक अर्थ रखेगा। बीज उद्योग का दस प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी का लक्ष्य एक बड़ी औद्योगिक महत्वाकांक्षा है। लेकिन उसकी वास्तविक कसौटी बाजार का आकार नहीं, किसान की स्थिति होगी। भारत को ऐसा बीज तंत्र चाहिए जिसमें निजी अनुसंधान की गति, सार्वजनिक विज्ञान की जिम्मेदारी और किसान का अधिकार—तीनों साथ चलें। आखिर बीज की मुट्ठी छोटी है, लेकिन उसमें देश की खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और किसान की उम्मीदें समाई हैं। बाजार बढ़े तो अच्छी बात है; मगर यह बढ़ोतरी ऐसी हो जिसमें किसान की निर्भरता नहीं, उसकी क्षमता, विकल्प और अधिकार बढ़ें।

लेखक-कुमार कृष्णन

रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ की तैयारियों के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई तीन समितियां

मंत्रियों-विधायकों को मिली जिम्मेदारी

राजधानी दिल्ली में आने वाले आस्था के बड़े पर्वों रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा को भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीनों पर्वों के लिए तीन अलग-अलग विशेष समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की कमान मंत्रियों, विधायकों और समाजसेवियों को सौंपी गई है।

नई दिल्ली,वेब वार्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन समितियों का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और सुचारु व्यवस्था उपलब्ध कराना है। सरकार चाहती है कि दिल्ली में ये पर्व श्रद्धा, अपनत्व और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाएं और आयोजन समितियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

...और सौहार्द का माहौल बना रहे

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने वाले आस्था के पर्व हैं। इनसे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालु पूरी भक्ति के साथ अपने पर्व मना सकें और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूरी करना है ताकि सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और सौहार्द का माहौल बना रहे।

रामलीला समिति की कमान मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह को रामलीला आयोजनों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष समाज कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, सहकारिता एवं निर्वाचन मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह बनाए गए हैं। इस समिति में विधायक अशोक गोयल, अनिल कुमार शर्मा, श्याम शर्मा, संजय गोयल और संदीप सहरावत सदस्य होंगे, जबकि सचिव, राजस्व-सह-मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे।

समिति की मुख्य जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत रामलीला के लिए जरूरी एनओसी जारी करवाना होगी। इसके अलावा रामलीला स्थलों पर पीने के पानी, चिकित्सा सहायता, एंबुलेंस, अग्निशमन सेवा, सुरक्षा, मोबाइल शौचालय, यातायात प्रबंधन, सफाई, फॉगिंग और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना भी इसी समिति का काम होगा। समिति रामलीला के मंच से पर्यावरण संरक्षण, वोकल फॉर लोकल, स्वच्छता, जल संरक्षण, स्वदेशी और नशा मुक्त भारत अभियान जैसे जनहित के संदेशों को भी बढ़ावा देगी।

दुर्गा पूजा की तैयारियों के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कानून एवं न्याय, श्रम, रोजगार, विकास, कला-संस्कृति भाषा तथा पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा करेंगे। समिति में विधायक शिखा रॉय और नीरज बसोया के साथ सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भट्टाचार्य, देवदत्त भारद्वाज और अरुण मुखर्जी सदस्य के रूप में शामिल हैं। यह समिति भी पूजा स्थलों पर सभी नागरिक सुविधाएं, सुरक्षा और एनओसी की व्यवस्था देखेगी। इसके अलावा, दुर्गा पूजा के लिए विशेष रूप से मूर्तियों के विसर्जन हेतु कृत्रिम और अस्थायी तालाबों की व्यवस्था करना और विसर्जन के बाद अवशेषों की सफाई सुनिश्चित करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी।

छठ पूजा के लिए भी मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में ही समिति बनाई गई है। इसमें विधायक अभय कुमार वर्मा, चंदन कुमार चौधरी, संदीप सहरावत, दीपक चौधरी और सामाजिक कार्यकर्ता संतोष ओझा सदस्य होंगे। सचिव, राजस्व-सह-मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे। छठ समिति घाटों और आयोजन स्थलों पर पानी, चिकित्सा, एंबुलेंस, सुरक्षा, सफाई और बिजली जैसी सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी और सिंगल विंडो सिस्टम से एनओसी दिलाने में मदद करेगी।

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को बारिश-आंधी का अलर्ट

तीन दिन तक छाए रहेंगे बादल

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश का असर अब दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर भी दिखाई देने लगा है। शनिवार सुबह से ही दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 26 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर के लिए बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के ताजा पूवार्नुमान के मुताबिक, 26 और 27 सितंबर को सामान्य तौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के स्थानीय पूवार्नुमान के अनुसार, 26 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस दिन सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। सुबह से लेकर पूर्वाह्न, दोपहर और शाम तक अलग-अलग समय पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 27 सितंबर को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। आईएमडी के पूवार्नुमान में इस दिन अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान सामान्य तौर पर बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम बारिश की संभावना है। सुबह, पूर्वाह्न, दोपहर और शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

28 सितंबर को भी बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि बारिश की तीव्रता कम होगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस दिन हल्की बारिश का अनुमान है और कोई मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। वहीं 29 सितंबर को मौसम में धीरे-धीरे सुधार की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

बन सकती है आशंका

मौसम विभाग के 26 सितंबर के उप-विभागीय पूवार्नुमान में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी है। 27 सितंबर को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। इसके चलते उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली-एनसीआर में भी बादल और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। बारिश और तेज हवाओं के चलते सड़क यातायात प्रभावित होने, जलभराव तथा बिजली से जुड़ी दिक्कतों की आशंका बन सकती है।

संक्षिप्त वार्ता

दहेज केस में फरार चल रहे आरोपी को द्वारका पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के द्वारका जिले की एंटी-जेल बेल एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेल की टीम ने दहेज के एक मामले में ट्रायल से भाग रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जितेंद्र (33) निवासी रूप नगर, दिल्ली के रूप में हुई है। उसे 4 अक्टूबर 2024 को कोर्ट की एमएस वैशाली सिंह, एलडी जेएमएफसी, साउथ-वेस्ट, द्वारका कोर्ट द्वारा एफआईआर कर थाना मोहन गार्डन के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था।

लॉक तोड़कर चुराते थे वाहन, शाहदरा पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। शाहदरा जिले की गांधी नगर पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की दो होंडा एक्टिवा स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, 9 सितंबर को गांधी नगर थाने में राजगढ़ कॉलोनी से स्कूटी चोरी होने की ई-एफआईआर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 8 सितंबर को उनकी स्कूटी चोरी हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी शाहदरा की निगरानी, एसीपी गांधी नगर के मार्गदर्शन और एसएचओ इंस्पेक्टर राज कुमार की देखरेख में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में एएसआई राहुल, हेड कांस्टेबल अभय पंवार, जितेंद्र, प्रमोद, विजयपाल और कांस्टेबल प्रिंस शामिल थे।

चित्रों में दर्शाया ध्यान, मौन का अनुभव

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। ओशो नव-संन्यास दिवस के अवसर पर ओशो धाम, नजफगढ़ के पास 27 सितंबर तक तीन दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान शनिवार को चित्रकार मा देव अनंती (अलका सिंह) के चित्रों की प्रदर्शनी द डिवाइन विदिन का उद्घाटन शनिवार को मा धर्म ज्योति और स्वामी चैतन्य कीर्ति ने किया। प्रदर्शनी में तेल और एक्रेलिक रंगों से बनाए गए सात चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें ध्यान, मौन, प्रेम, जागरुकता और भीतर की शांति जैसे अनुभवों को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। आयोजकों के अनुसार, चित्रकार के लिए चित्रकारी ध्यान और आत्म-अन्वेषण की अभिव्यक्ति है। मा देव अनंती की ओशो यात्रा 1982 में शुरू हुई। 2011 के बाद ध्यान और चित्रकारी उनके जीवन का हिस्सा बन गए। प्रदर्शनी 26 अक्टूबर तक सभी के लिए खुली रहेगी।

युवा बड़े सपने देखें, सकारात्मक रहें और विवेक से निर्णय लें : सतीश दुआ

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर आयोजित व्याख्यान में लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए तीन सूत्र दिए- बड़े सपने देखें, सकारात्मक रहें और विवेकशील बनें। साथ ही उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, सही और गलत के बीच अंतर समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लें, तथा आवश्यकता पड़ने पर आसान रास्ते के बजाय कठिन लेकिन सही मार्ग चुनें। एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित 'राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका' विषयक इस व्याख्यान में लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने भारतीय सेना में अपने लंबे अनुभवों और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियानों से जुड़े प्रसंग साझा किए।

आसनन ऐप बताएगा योगासन की सही मुद्रा

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) दिल्ली ने मिलकर आसनन नाम से निःशुल्क योग एवं संज्ञानात्मक स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सही तरीके से योगासन करने में मदद करने के साथ ही स्मृति और ध्यान पर भी काम करने की सुविधा देता है। इसमें कंप्यूटर विजन और पोज एस्टिमेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह योग करते समय शरीर के प्रमुख जोड़ों की गतिविधियों को ट्रैक कर मुद्रा का विश्लेषण करता है।

16 लाख विद्यार्थियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर संवाद करेगा सीआईएससीई

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआईएससीई) कक्षा 6 से 12 तक के करीब 16 लाख विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर राष्ट्रीय संवाद से जोड़ेगा। इसके तहत 3300 से अधिक संबद्ध स्कूलों और करीब 32 हजार शिक्षकों की भागीदारी होगी। पहल के तहत विद्यार्थियों की चिंताओं और अनुभवों को स्कूल स्तर से क्षेत्रीय और फिर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया जाएगा। सीआईएससीई स्टूडेंट मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग कॉन्क्लेव 2026 की शुरूआत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 10 अक्टूबर से होगी।

दिल्ली में खुला एनसीआर का सबसे बड़ा ऑटसेमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, सीएम ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के वाहन चालकों को अब अपने वाहनों की फिटनेस कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली के बुराड़ी में एनसीआर का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) का संचालन शनिवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया। पांच लेन वाले इस एटीएस में सालाना एक लाख वाहनों की फिटनेस जांच हो सकेगी। इनमें 40 हजार भारी मोटर वाहन और 60 हजार हल्के मोटर वाहन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बुराड़ी एटीएस में वाहन की फिटनेस का आकलन वैज्ञानिक और स्वचालित प्रक्रिया से होगा। जांच के दौरान ब्रेक की दक्षता, सस्पेंशन, हेडलाइट, साइड-स्लिप, उत्सर्जन स्तर और वाहन के निचले हिस्से समेत विभिन्न मानकों की जांच की जाएगी। इसका मकसद

फिटनेस जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ सड़क पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा और प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केवल सर्दियों में किए जाने वाले अस्थायी उपाय पर्याप्त नहीं हैं। सरकार प्रदूषण नियंत्रण को पूरे वर्ष चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देख रही है। इसके तहत परिवहन, हरित क्षेत्र, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कचरा प्रबंधन और तकनीक आधारित निगरानी जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन फिटनेस व्यवस्था को बेहतर बनाना भी प्रदूषण नियंत्रण की इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। निर्धारित फिटनेस और उत्सर्जन मानकों का पालन कराने से सड़क पर चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नंद नगरी, तेखंड और बुराड़ी में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन शुरू होने के बाद दिल्ली में स्वचालित वाहन फिटनेस जांच की क्षमता सालाना 2.5 लाख से अधिक वाहनों की हो गई है। इससे खासतौर पर व्यावसायिक वाहनों को आधुनिक फिटनेस जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पहले तीन सितंबर को तेहखंड में 72 हजार वाहनों की सालाना फिटनेस जांच क्षमता वाले एटीएस की शुरूआत की गई थी। अब बुराड़ी केंद्र शुरू होने से इस व्यवस्था का विस्तार उत्तर दिल्ली की तरफ भी हुआ है।

अक्षरधाम के पास दो वाहन चोर गिरफ्तार, तीन चोरी की बाइक-स्कूटी बरामद

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। पूर्वी जिले की मंडावली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के तीन दोपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिससे तीन अलग-अलग थानों में दर्ज वाहन चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है।

पुलिस उपायुक्त (पूर्वी जिला) राजीव कुमार ने बताया कि मंडावली थाने की टीम खेल गांव रोड, अक्षरधाम के पास गश्त और एहतियाती चेकिंग कर रही थी। टीम में हेड कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल फिरोज शामिल थे। यह पूरी कार्रवाई एसीपी मयूर विहार की देखरेख और एसएचओ मंडावली के नेतृत्व में की गई। 22 सितंबर 2026 को गश्त के दौरान पुलिस ने दो युवकों को संदिग्ध तरीके से दोपहिया वाहन चलाते देखा। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि उनके पास मौजूद गाड़ी मंडावली इलाके से ही चोरी हुई थी और इस संबंध में ई-एफआईआर दर्ज है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमन (20 वर्ष) और अमान (18 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों सीलमपुर के चौहान बांगर इलाके के रहने वाले हैं। पूछताछ में दोनों ने वाहन चोरी में अपनी भूमिका कबूल कर ली। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने दो और चोरी की दोपहिया गाड़ियां बरामद कीं।

बरामदगी में पहली गाड़ी डीएल7एससीबी सीरीज की है, जो मंडावली थाने के मामले से जुड़ी है। दूसरी डीएल9एससीयू सीरीज की है, जो उत्तम नगर थाने में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। तीसरी डीएल7एसबीटी सीरीज की है, जो कमला मार्केट थाने के मामले में चोरी हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आरोपी अमन पहले भी स्नैचिंग और लूट के तीन मामलों में शामिल रहा है।

पुलिस के अनुसार, मोटर वाहन चोरी और सड़क पर होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के लिए इलाके में सघन गश्त, निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाने का काम लगातार जारी है। मंडावली पुलिस की इस त्वरित और समन्वित कार्रवाई को पूर्वी जिले में अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।

रंजीत नगर पुलिस ने ड्रग पेडलर को दबोचा, 1 किलो गांजा बरामद

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। सेंट्रल दिल्ली के रंजीत नगर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सतर्क पेट्रोलिंग टीम ने आरोपी के पास से 1026.8 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, 25 सितंबर को हेड कांस्टेबल सीताराम, कांस्टेबल ललित और कांस्टेबल सुमित इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। सुबह करीब 10:25 बजे जब टीम पटेल नगर से दिल्ली कैंट की ओर शादीपुर फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन के पास पहुंची, तो उन्होंने एक व्यक्ति को हाथ में पॉलीथीन बैग लिए हुए देखा।

निगम के सामुदायिक केंद्रों में लगेंगे केंद्रीकृत वातानुकूलित प्रणाली

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। गर्मी के मौसम में दिल्ली नगर निगम के सामुदायिक केंद्रों में आयोजन करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। निगम गर्मी में से राहत देने के लिए अपने सामुदायिक केंद्रों में केंद्रीकृत वातानुकूलित (एसी) प्रणाली लगाने जा रहा है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से इसकी शुरूआत होगी।

निगम की योजना के अनुसार, शाहदरा दक्षिणी (पूर्वी दिल्ली) जोन में आने वाले दो सामुदायिक केंद्रों को इस योजना के प्रारंभिक चरण में शामिल किया गया है। इनमें सात-ब्लॉक त्रिलोकपुरी स्थित सामुदायिक केंद्र और 17-ब्लॉक त्रिलोकपुरी स्थित सामुदायिक केंद्र शामिल है। इन दोनों केंद्रों में केंद्रीकृत वातानूकुलित प्रणाली लगाने पर करीब 1.20 करोड़ रुपये की लागत आएगी। निगम ने इस काम को चार माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

अधिकारियों के मुताबिक, अभी निगम के 249 सामुदायिक केंद्र हैं। इनमें से चुनिंदा में विंडो व स्प्लिट एसी लगे हैं। अधिकतर बिना एसी के सामुदायिक केंद्र हैं। ऐसे में शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों के दौरान आयोजक को अपने स्तर पर कूलिंग व्यवस्था करनी पड़ती है। इस समस्या को देखते हुए केंद्रीकृत वातानूकुलित प्रणाली लगने के की योजन पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

दक्षिणपूर्वी दिल्ली रेस लगा रही एक कार ने दो वाहनों को टक्कर मारी

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सुखदेव विहार में शनिवार सुबह एक तेज रफ़्तार कार ने दो गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे 45 वर्षीय एक ऑटो-रिक्शा चालक की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि सुबह सात बजे यह हादसा हुआ तथा सवा सात बजे इस घटना की सूचना उसे दी गयी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मोहम्मद कलाम के रूप में हुई तथा उसके ऑटो रिक्शा को भी कार ने टक्कर मारी थी। उसने बताया कि घायल व्यक्ति की पहचान सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास रहने वाले मो. बबलू के तौर पर हुई है। आरंभिक जानकारी के मुताबिक, कार ने कथित तौर पर पहले एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी और उसके बाद एक साइकिल रिक्शा से टकरा गई। घटनास्थल से लगभग 10 से 20 मीटर की दूरी पर मौजूद एक चाय वाले ने पहले पुलिस को बताया था कि दो कारें कथित तौर पर ह्यरेसह्न कर रही थीं, तभी उनमें से एक कार बेकाबू हो गई और दूसरी गाड़ियों से जा टकराई।

दिल्ली में विस्तार पर विचार कर रही जन सुराज, प्रशांत किशोर को सौंपा जाएगा प्रस्ताव

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। जन सुराज पार्टी दिल्ली की राजनीति में उतरने की संभावना तलाश रही है और राष्ट्रीय राजधानी में उसके समर्थक बांकीपुर उपचुनाव में जीत के लिए पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को सम्मानित करने के दौरान रविवार को उनके समक्ष दिल्ली इकाई के गठन संबंधी प्रस्ताव रखेंगे।

इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में रहने वाले पार्टी से जुड़े बिहार के लोग कर रहे हैं। जन सुराज की कोर समिति के सदस्य कुमार शांतनु ने कहा कि किशोर की राजनीतिक सोच से जुड़े समर्थक दिल्ली में पार्टी की इकाई गठित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव लड़ने की दिशा में कोई भी कदम यहां पार्टी की संभावनाओं का आकलन करने के बाद ही उठाया जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में वनस्पति विज्ञान पढ़ाने वाले शांतनु ने कहा, दिल्ली में जन सुराज से जुड़े लोगों की मांग है कि पार्टी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराए लेकिन रविवार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बांकीपुर में जीत के लिए किशोर को सम्मानित करना है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है लेकिन यदि कोई इसमें शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है।

शांतनु ने कहा कि बक्सर के पूर्व सांसद के.के. तिवारी के बेटे एवं अधिवक्ता तथागत हर्षवर्धन और हिमाचल प्रदेश के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जे. पी. सिंह के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। दोनों ने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जन सुराज के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। दिल्ली में इकाई गठित होने पर यह पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा क्योंकि अब तक उसका संगठन और चुनावी गतिविधियां मुख्य रूप से बिहार तक सीमित रही हैं। दिल्ली में पार्टी के समर्थक चुनाव लड़ने की योजना घोषित करने के बजाय यहां औपचारिक संगठन खड़ा करने के लिए किशोर की मंजूरी चाहते हैं।

विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके पूर्व चुनाव रणनीतिकार किशोर ने बिहार में शिक्षा, रोजगार और शासन के मुद्दों पर अभियान चलाते हुए जन सुराज की शुरूआत की थी। संगठन के राजनीतिक दल का रूप लेने से पहले उन्होंने कई महीने राज्यभर की यात्रा की थी। जन सुराज के लिए पहला बड़ा चुनावी इम्तिहान 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव था। पार्टी ने 238 सीट पर चुनाव लड़ा था लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। इसके बाद ये सवाल उठे थे कि किशोर के अभियान को जनता से मिल रहे समर्थन को क्या वास्तव में मतों में बदला जा सकता है। किशोर उस चुनाव में स्वयं उम्मीदवार नहीं थे। इसके बाद इस साल अगस्त में हुए बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी को बिहार विधानसभा में पहली सीट मिली और उम्मीदवार के रूप में किशोर ने भी पहली चुनावी जीत दर्ज की।

दयालपुर में 3.5 लाख रुपए की डकैती के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद

नॉर्थ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने डकैती के एक सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

आरोपी को हरियाणा के आईएमटी मानेसर इलाके से पकड़ा गया है और उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है।

पुलिस के अनुसार, 2 अगस्त 2026 को दयालपुर के सेरपुर चौक के पास डकैती की वारदात हुई थी। शिकायतकर्ता रवि सिंह जादौन और उनके कर्मचारी मोहित से 4-5 बदमाशों ने देसी पिस्तौल दिखाकर करीब 3.50 लाख रुपए और दो मोबाइल फोन लूट लिए थे।

इस मामले में दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक बाल अपचारी (सीसीएल) और शिकायतकर्ता का एक कर्मचारी भी शामिल था। उनके पास से 15,000 रुपए बरामद किए गए थे लेकिन इस वारदात में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने वाले दो आरोपी फरार चल रहे थे।

फरार आरोपियों की तलाश के लिए नॉर्थ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने खास खुफिया जानकारी जुटाई और लगातार तकनीकी निगरानी रखी। इसी कड़ी में 24 सितंबर को स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक विशेष ऑपरेशन चलाकर फरार आरोपी मन्नू उर्फ ऋषि (उम्र 24 साल) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मन्नू गामरी एक्सटेंशन, भजनपुरा, दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी पिस्तौल बरामद की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी मन्नू उर्फ ऋषि पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट से जुड़े 3 मामले पहले से दर्ज हैं। इस मामले में अभी एक और आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और आगे की जांच जारी है।

समयपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक मोल्डिंग इकाई में आग, तीन लोग मामूली रूप से झुलसे

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के समयपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार देर रात प्लास्टिक मोल्डिंग की एक इकाई में आग लगने से तीन लोग मामूली रूप से झुलस गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के फेज-2 में रात करीब साढ़े बाहर बजे आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। दिल्ली अग्निशमन सेवा को आग लगने के संबंध में कई सूचनाएं मिलीं, जिसके बाद कुल 15 दमकल इकाइयों को मौके पर तैनात किया गया। इनमें ह्यब्रोंटो एरियल लैडर प्लेटफॉर्मह्न भी शामिल था। अधिकारियों के अनुसार, यह इकाई एक ऐसी इमारत में स्थित थी जिसमें तहखाना, भूतल, पहली और दूसरी मंजिल है तथा छत पर एक अस्थायी ढांचा भी बना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर देर रात तीन बजकर 15 मिनट पर काबू पा लिया गया। इसके बाद प्रशीतन अभियान संचालित किया गया। इस घटना में तीन लोग धर्मवीर (32), मोहम्मद सरुख (41) और अमित (34) मामूली रूप से झुलस गए। अधिकारियों के मुताबिक, दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही आम लोगों ने तीनों को आंबेडकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।

संक्षिप्त वार्ता

भाजपा सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं,बल्कि पूरे कार्यकाल जनता के बीच रहती है: पासवान

वेब वार्ता, देवरिया

देवरिया जिला मुख्यालय से बीस किलोमीटर दूर रूद्रपुर में नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार एक कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि भाजपा केवल चुनाव जीतकर सरकार बना लेने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे कार्यकाल आमजन के बीच जाकर जनहित की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है।

श्री पासवान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष का कार्यकाल निर्बाध रूप से पूरा किया है। उनके जन्मदिन और सेवा भाव के अवसर पर उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस एक माह के अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभ दिलाया जाए। गांव स्तर पर छूटे हुए पात्रों की खोजकर कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही विभिन्न स्थानों पर टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

कुशीनगर में ऑरेंज अलर्ट के दृष्टिगत आमजन के लिए एडवा-इजरी जारी

वेब वार्ता, कुशीनगर

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद कुशीनगर ऑरेंज अलर्ट में है। अगले दो दिनों में मध्यम से तीव्र गति की वर्षा होने की संभावना को देखते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक एडवाइजरी जारी की गई है। आकाशीय बिजली से बचाव के संबंध में नागरिकों से अपील की गई है कि आकाशीय बिजली गिरने की सूचना अथवा संभावना के दौरान कच्चे एवं जीर्ण–शीर्ण मकानों में रहने से बचें। सुरक्षित स्थान उपलब्ध न होने पर पंचायत भवन आदि सुरक्षित स्थानों पर शरण लें।

बादलों के गरजने एवं चमकने के समय घरों से बाहर न निकलें तथा सुरक्षित स्थान पर रहें। यदि रास्ते में अचानक बादल गरजने एवं चमकने की स्थिति उत्पन्न हो तो तत्काल नजदीकी सुरक्षित स्थान पर रुकें। बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे किसी भी दशा में शरण न लें। विद्युत पोल, खुले विद्युत तारों एवं अन्य विद्युत उपकरणों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें तथा टीवी एवं रेडियो के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहें।

विद्युत कंट्रोल रूम में भरा पानी, 500 गांव की विद्युत आपूर्ति ठप

वेब वार्ता, बलरामपुर

उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में तूफानी बरसात से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। तुलसीपुर देहात विद्युत उपकेंद्र के कंट्रोल रूम में पानी भर जाने से आठ फीडरों से जुड़े करीब 500 गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। इसके अलावा क्षेत्र में 22 स्थानों पर विद्युत खंभे उखड़ने की सूचना है।

लगातार हो रही बारिश के कारण तुलसीपुर विद्युत उपकेंद्र, तुलसीपुर देहात विद्युत यार्ड और विद्युत कंट्रोल रूम में भी पानी भर गया है। इससे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गुल होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण विद्युत लाइनों और खंभों को हुए नुकसान से स्थिति और गंभीर हो गई है।

परिजनों से बिछड़े बच्चों की वापसी के बाद भी उनका पूरा ख्याल रखेगी प्रदेश की योगी सरकार

लखनऊ, 26 सितंबर (वेब वार्ता)

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल संरक्षण की व्यवस्था को इस सोच के साथ मजबूत किया है कि बच्चे को केवल परिवार तक पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जरूरत के अनुसार उसकी काउंसलिंग, संरक्षण और पुनर्वास भी सुनिश्चित किया जाए। बाल हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से संकट में फंसे बच्चों तक मदद पहुंचाने के साथ उनकी सुरक्षित वापसी और आगे की जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गुमशुदगी या संकट की परिस्थितियों से गुजरने वाले बच्चे कई बार मानसिक और भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं। ऐसे में जरूरत के अनुसार काउंसलिंग उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे की स्थिति और जरूरत का आकलन कर उसे आवश्यक संरक्षण एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ताकि परिवार में वापसी के बाद बच्चे को सामान्य जीवन में लौटने के लिए जरूरी भावनात्मक सहारा मिल सके।

दो दिन से लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे मुरझाए

फतेहपुर, 26 सितंबर (वेब वार्ता)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में तीन दिन से लगातार हो रही भारी–बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलें सड़ कर बर्बाद हो रही हैं। धान की फसल हवा के झोंकों से गिर गई है। वहीं सब्जी की फसलें, तिल, अरहर ज्वार–बाजरा सहित अन्य फसलों को भी भारी नुकसान से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ने लगी है।

जिले में सब्जी की फसलों में लौकी, तरोई, करेला, चिचिड़ा, भिंडी, गोभी, की बहुतायत में की जाती हैं। इन फसलों को भारी नुकसान हुआ है ,वहीं धान, तिल, अरहर ज्वार–बाजरा की फसलों को भी बर्बाद हो गई हैं। दो दिन से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है।

पितृ पक्ष शुरू, पितरों के स्मरण और तर्पण के साथ निभाई जा रही सनातन परंपरा

पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर, घर-घर में तर्पण, श्राद्ध और अन्नदान की तैयारियां

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पितृ पक्ष शनिवार से शुरू हो गया। इसके साथ ही घर-घर में अपने पितरों के स्मरण, तर्पण और श्राद्ध से जुड़ी धार्मिक परंपराओं का क्रम शुरू हो गया है। पितृ पक्ष को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का विशेष अवसर माना जाता है।

पितृ पक्ष के प्रथम दिन श्रद्धालुओं ने अपने पितरों का स्मरण करते हुए विधि-विधान से जल अर्पित किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान तथा ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष महत्व माना गया है।

सनातन परंपरा में पितृ ऋण की अवधारणा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि मनुष्य अपने पूर्वजों से प्राप्त जीवन, संस्कार और परंपराओं के प्रति कृतज्ञ रहता है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए पितृ पक्ष में श्रद्धापूर्वक तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं।

पुरानी परंपराओं के अनुसार, कई परिवारों में पितृ पक्ष के दौरान कौए, गाय, कुत्ते और अन्य जीवों को भोजन कराने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों, साधु-संतों अथवा जरूरतमंदों को भोजन और अन्नदान करने की परंपरा भी प्रचलित है। इन सभी परंपराओं के पीछे श्रद्धा, सेवा, दान और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रमुख माना जाता है।

पितृ पक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और पूर्वजों को याद करने का अवसर भी है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बीच यह परंपरा नई पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास, संस्कारों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का माध्यम बनती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष में श्रद्धापूर्वक किया गया तर्पण और श्राद्ध पितरों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसी भावना के साथ लोग इन दिनों अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

पितृ पक्ष का संदेश यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लें, अपनी जड़ों और उन पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिनके त्याग और संस्कारों से हमारी पहचान बनी है।

पितरों के निमित्त बटुक ब्राह्मणों को करा रहे भोजन

पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराने की पुरानी परंपरा के तहत इन दिनों काफी श्रद्धालु हनुमान धारा मंदिर में संचालित महंत श्री गोपी दास जी वेद विद्या संस्कृति गुरुकुलम पहुंच रहे हैं। यहां वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे करीब 70 बटुक ब्राह्मण विद्यार्थियों को श्रद्धालु अपने पितरों की स्मृति में भोजन करा रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक भोजन और अन्नदान करना पुण्यकारी माना जाता है। इसी भावना के साथ श्रद्धालु बटुक ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं।

चलती ट्रेनों में यात्रियों के सामान पर चोरों का हाथ साफ

ललितपुर। ट्रेनों में यात्रियों के सामान की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। ललितपुर जीआरपी थाना क्षेत्र में चलती ट्रेनों में चोरी की दो घटनाएं सामने आई हैं। सात सितंबर को यात्रियों के सोने का फायदा उठाकर चोर पांडिचेरी एक्सप्रेस और पंजाब मेल से बैग पार कर ले गए। जीआरपी ने दोनों मामलों में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

22404 पांडिचेरी एक्सप्रेस में नागपुर निवासी मो. इयूसुब कुरैशी पत्नी के साथ नई दिल्ली से नागपुर जा रहे थे। एस-06 कोच में यात्रा के दौरान दोनों सो गए। पत्नी का सिरहाने रखा काले रंग का हैंडबैग ललितपुर के पास गायब हो गया। बैग में मोबाइल, 1,500 रुपये, तीन घड़ियां, चांदी की अंगूठी, आधार-वोटर कार्ड, बैंक एटीएम कार्ड और अन्य सामान था।

पांडिचेरी एक्सप्रेस से मोबाइल-नकदी, पंजाब मेल से पेंशन दस्तावेज चोरी

पंजाब मेल से पेंशन के दस्तावेज गायब

12138 पंजाब मेल में दिल्ली कैंट निवासी राकेश कुमार महतो नई दिल्ली से नासिक रोड जा रहे थे। बी-02 कोच में सीट के नीचे रखा पिट्ठू बैग ललितपुर के पास गायब हो गया। बैग में पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, 1,500 रुपये, मोबाइल, कपड़े और पत्नी समेत उनके आधार-पैन कार्ड रखे थे।

यात्रियों की सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

चलती ट्रेनों में यात्रियों के सोते समय सामान चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना पड़ रहा है। दोनों मामलों में जीआरपी ने बीएनएस की धारा 305(सी) के तहत एफआईआर दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

गणपति विसर्जन के दौरान रामगंगा में डूबने लगा श्रद्धालु

मुस्तैद गोताखोर ने छलांग लगाकर बचाई जान

वेब वार्ता, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित कटघर क्षेत्र के कृष्णा घाट पर गणपति विसर्जन के दौरान उस समय बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब रामगंगा नदी में गणपति प्रतिमा विसर्जित करने उतरा एक व्यक्ति अचानक अनियंत्रित होकर गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। अचानक घटे इस हादसे से मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा–तफरी मच गई। शोर सुनकर नदी पर ड्यूटी कर रहे गोताखोर ने बिना समय गंवाए पानी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद डूब रहे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे समय रहते उसकी जान बच गई। घाट पर मौजूद लोगों ने इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गोताखोर की मुस्तैदी साफ देखी जा सकती है। इस घटना ने एक बार फिर नदी तटों पर विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और व्यक्तिगत सावधानी बरतने की जरूरत को उजागर किया है, क्योंकि बिना सुरक्षा उपायों के गहरे पानी में उतरना जानलेवा साबित हो सकता है।

कुशीनगर में आर टी ओ विभाग ने जिले के दस हजार वाहनों को चिन्हित कर स्वामियों को दिया नोटिस

वेब वार्ता, कुशीनगर। कुशीनगर जिले में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। एआरटीओ ने जिले में ऐसे करीब 10 हजार वाहनों को चिह्नित करते हुए उनके स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है।

नियमों का पालन न करने वाले इन वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर तय समय में जवाब मांगा जाएगा, जवाब नहीं देने पर नियम के मुताबिक आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

जिले में परिवहन विभाग की ओर से बार–बार चेतावनी और अपील के बाद भी छोटे–बड़े करीब 10 हजार वाहन बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जबकि परिवहन विभाग में कुल पांच लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें बाइक, तीन पहिया, चार पहिया और भारी व व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। विभाग और शासन के निर्देशों के बावजूद हजारों वाहन स्वामी अब भी साधारण नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जिससे सुरक्षा जांच व यातायात प्रबंधन में परेशानी आ रही है।

विभाग के जिम्मेदारों के मुताबिक, वाहनों की चोरी रोकने,अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सड़कों पर सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है।

कुशीनगर में गंडक नदी का डिस्चार्ज तीन लाख से ऊपर पहुचा

वेब वार्ता, कुशीनगर। कुशीनगर में गंडक नदी का डिस्चार्ज तीन लाख से ऊपर पहुच गया है। डिस्चार्ज बढने से तटवर्ती गांवों में चिंता बढ गई है। जिला प्रशासन सतर्क मूड में है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। बांधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वाल्मीकिनगर बैराज से शनिवार को पानी का डिस्चार्ज शाम 4 बजे 3,00,400 क्यूसेक पहुंच गया। नेपाल में बाढ़ से सतर्क रहने की अपील वाला वीडियो वायरल होने से तटवर्ती गांवों में चिंता बढ़ गई है। गंडक नदी के बढ़ते डिस्चार्ज के बीच छितौनी तटबंध के विभिन्न हिस्सों में 300 से अधिक रेनकट लोगों की चिंता बढ़ाने वाले हैं। वहीं, एपी तटबंध के एक ठोकर के नोज के धंसने की सूचना है।

फार्म हाउस गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग से जांच की मांग

किसान मोर्चा ने फार्म हाउसों की भूमिका पर उठाए सवाल

वेब वार्ता, अमरोहा

जिले के हसनपुर क्षेत्र स्थित एक विधायक के चर्चित फार्म हाउस में हरियाणा की 24 वर्षीय युवती के साथ हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना से क्षेत्र में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस गंभीर प्रकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन (संयुक्त मोर्चा) ने राष्ट्रीय महिला आयोग और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र भेजकर मामले का स्वतः संज्ञान लेने और समयबद्ध निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग की है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम पौसरा में आयोजित किसान पंचायत में इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। पंचायत को संबोधित करते हुए नरेश चौधरी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों के साथ किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हाईटेक फार्म हाउसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऊंची दीवारों, कैमरों और पहरेदारी से घिरे इन स्थलों पर संदिग्ध गतिविधियों का होना चिंताजनक है। विधायक के फार्म हाउस में घटी इस वारदात के बाद केयरटेकर व चौकीदार पर जिम्मेदारी डालकर अनभिज्ञता जताने को उन्होंने आश्चर्यजनक बताया और मांग की कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और फार्म हाउस के सुरक्षा चक्र के सभी पहलुओं को जांच के दायरे में लाया जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहतकर और उत्तर प्रदेश डीजीपी को भेजे गए प्रार्थना पत्र में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई, फॉरेंसिक साक्ष्यों के तत्काल संरक्षण तथा घटना में शामिल सहयोगियों या किसी भी अन्य व्यक्ति की भूमिका की विस्तृत जांच सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त दोषी पाए जाने वाले पुलिस या प्रशासनिक कर्मियों के विरुद्ध त्वरित विभागीय कार्रवाई करने तथा पीड़िता और उसके परिवार को त्वरित चिकित्सकीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक, सुरक्षा सहायता एवं नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। संगठन ने राष्ट्रीय राजमार्ग–9, राज्य मार्ग–51 और आसपास के संपर्क मार्गों पर संचालित ऐसे सभी फार्म हाउसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

इस अवसर पर 21 लोगों की ग्राम कार्यकारिणी घोषित कर मुन्त्याज चौधरी को ग्राम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।

तर्कसंगत एंटीबायोटिक जागरूकता दिवस का हुआ आयोजन

बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक का सेवन गंभीर खतरा

वेब वार्ता, कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (जीएसवीएम) मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में ह्वतर्कसंगत एंटीबायोटिक जागरूकता दिवसह्ल का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने सचेत किया कि बिना डॉक्टरी परामर्श के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक साबित हो सकता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र गौतम ने कहा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) एक गंभीर चुनौती बना रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक और अनुचित उपयोग के कारण बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आअसीएमआर) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि भारत में एएमआर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। इसके चलते अब निमोनिया, सेप्सिस और यूटीआई (मूत्र मार्ग संक्रमण) जैसे गंभीर संक्रमणों के इलाज में भी प्रभावी दवाओं का चयन बेहद कठिन हो गया है।

वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. यशवंत के. राव ने अभिभावकों से विशेष अपील करते हुए कहा कि बच्चों में सर्दी-खांसी और सामान्य वायरल बुखार में एंटीबायोटिक दवाओं की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये दवाएं वायरस पर असर नहीं करती हैं। बिना परामर्श के दवा देने से बच्चों की आंतों में मौजूद लाभदायक बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है और भविष्य के लिए दवा प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसी क्रम में डॉ. अमितेश यादव ने बताया कि जब संक्रमण प्रतिरोधी हो जाता है, तो मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। इससे इलाज की अवधि, जटिलताएं और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ जाते हैं। उन्होंने सख्त सलाह दी कि पुरानी बची हुई दवा का खुद से दोबारा इस्तेमाल करना या किसी अन्य व्यक्ति को देना बेहद खतरनाक है। इस दौरान कार्यक्रम में डॉ. नेहा अग्रवाल, डॉ. राहुल, डॉ. रश्मि सहित लगभग 35 वरिष्ठ चिकित्सकों एवं रेजिडेंट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक के विवेकपूर्ण उपयोग और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

पेड़ गिरने से रामपाल यादव गंभीर रूप से घायल लखनऊ में हो रहा इलाज

पचपेड़वा / बलरामपुर। थाना पचपेड़वा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोतीनगर (मतईडीह) निवासी 55 वर्षीय रामपाल यादव उर्फ घिर्रे पुत्रराम दुलारे शुक्रवार की शाम पेड़ की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल रामपाल यादव भाजपा बूथ अध्यक्ष रत्तीराम यादव के छोटे भाई बताए जा रहे हैं।

वेब वार्ता, कमर खान

परिजनों के अनुसार, रामपाल यादव जुड़िकुइयां में सहबाज प्रधान के कॉम्प्लेक्स में कॉस्मेटिक की छोटी दुकान चलाते हैं। शुक्रवार की शाम करीब सात बजे दुकान बंद कर वह घर लौट रहे थे। इसी दौरान फजले रहमानिया इंटर कॉलेज के पीछे बरगदवा मोतीनगर मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे खड़ा यूकेलिप्टस का मोटा पेड़ अचानक उनके ऊपर गिर पड़ा।

हादसे में रामपाल यादव पेड़ के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद परिजन उन्हें निजी एंबुलेंस से उपचार के लिए लखनऊ ले गए, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।

परिजनों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और रामपाल यादव का आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन सका है। घटना को दैवी आपदा बताते हुए प्रधान प्रतिनिधि नन्दकुमार पाण्डेय ने पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह (शैलू) से अहेतुक सहायता दिलाने की मांग की है।

कुछ ही घंटों में खुलवा दिये रास्ता

पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया जिसकी सूचना पाते ही नगर पंचायत अध्यक्ष रवि वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच कर तत्परता दिखाते हुए पेड़ को कटवा कर रास्ता कुछ ही घंटों में खुलवा दिए।

मुंडापांडे सीएचसी में सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन

वेब वार्ता, मुरादाबाद। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडापांडे में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विधायक ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल–चाल जाना और उन्हें फल वितरित किए। साथ ही शिविर में लगाए गए विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी स्टॉलों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

शिविर में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ–साथ नियमित स्वास्थ्य जांच और जन–जागरूकता बेहद आवश्यक है। उन्होंने आह्वान किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन–जन तक पहुँचाने के लिए सरकार और प्रशासन संकल्पित हैं, इसलिए आमजन को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। शिविर के दौरान तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय (टीएमयू) के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने लगभग 185 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक जांचें व निःशुल्क उपचार किया। इनमें 67 मरीजों की खून की जांच, 24 मरीजों का एक्स–रे, 60 लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग तथा 15 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

वीडियो से खुला राममंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, नहीं तो...

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस घटना का खुलासा एक वीडियो के माध्यम से हुआ था, जिसमें गणना कक्ष के बाथरूम में नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही थीं।

चार्जशीट के मुताबिक, 4 जून को गणना कर्मी आनंद चौधरी ने दिल्ली से अयोध्या ट्रेन से आ रहे रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपतराय को मोबाइल पर यह वीडियो और संदेश भेजकर चोरी की जानकारी दी थी। चंपतराय के निर्देश पर हुई जांच में बाथरूम से 2.25 लाख रुपये बरामद किए गए थे।

चार्जशीट में आगे बताया गया है कि 5 जून को चंपतराय के अयोध्या पहुंचने के बाद उनके आवास पर अनिल मिश्रा, गोपालराव और नरेंद्र ने लैपटॉप पर वह वीडियो देखा। गणना कर्मी मदन गोपाल निगम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 3 जून को ड्यूटी के दौरान उन्हें करुणेश पांडेय, अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा पर संदेह हुआ था। आरोप है कि ये लोग मेज के नीचे से नोटों की गड्डियां निकालकर अपनी कमर में छिपाते थे। पुलिस ने अपनी जांच में मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा और कॉल डिटेल रिकॉर्ड

(सीडीआर) को अहम साक्ष्य बनाया। डिलीट किए गए फुटेज को भी विशेषज्ञों की मदद से सफलतापूर्वक रिकवर किया गया। चार्जशीट के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में अविनाश शुक्ला 85 बार चढ़ावा राशि हटाकर अपने पास रखते और चार बार अन्य लोगों को रकम हटाने में मदद करते दिखाई दिए। करुणेश पांडेय भी दो बार रकम हटाते हुए कैमरे में कैद हुए।

इस मामले में नियुक्तियों की भी जांच की गई है। चार्जशीट के मुताबिक, अनुकल्प मिश्रा ने वर्ष 2025 में एसबीआई सैनिक सिक्योरिटी सर्विस से संपर्क कर लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडेय और अविनाश शुक्ला को गणना कर्मी के रूप में नियुक्त कराया था। बाद में रामशंकर यादव के भतीजे मनीष यादव को भी गणनाकर्मी नियुक्त कराया गया। पुलिस ने सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव टिन्नू पर भी लोकसेवक से संबंधित धाराएं लगाई हैं। चार्जशीट के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ और उनकी निशानदेही पर चोरी से बची रकम, अन्य मुद्रा तथा आभूषण बरामद किए गए। यह माल चंपतराय, गोपाल और ट्रस्ट के अन्य कर्मियों की मौजूदगी में सौंपा गया था। एक सहमति पत्र और सुपुर्दगीनामा तैयार कर बरामद माल को ट्रस्ट के लॉकर कक्ष में रखा गया, जहां यह एफआईआर दर्ज होने तक 21 दिनों तक चंपतराय की सुपुर्दगी में रहा। बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद लॉकर से यह सारा माल अपने कब्जे में ले लिया। सुभाष श्रीवास्तव ने पूछताछ में बताया कि उसे मिली रकम खर्च हो चुकी थी।

महत्वपूर्ण ख़बर

अमेरिका का खतरनाक प्लान: होर्मुज में लेजर हथियारों की तैयारी

- वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना हाई-एनर्जी लेजर हथियारों के इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन सिस्टम का इस्तेमाल ड्रोन और आने वाली क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए किया जा सकता है। खास बात यह है कि इन हथियारों को संचालित करने के लिए बदले हुए एक्सबोक्स गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

लेजर हथियारों की सबसे बड़ी खासियत यह बताई जाती है कि इन्हें चलाने के लिए हर बार अलग मिसाइल या इंटरसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ती। बिजली उपलब्ध रहने पर सिस्टम लगातार कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। इससे प्रत्येक हमले की लागत पारंपरिक इंटरसेप्टर की तुलना में कम हो सकती है। हालांकि, पूरे सिस्टम को विकसित और तैनात करने की लागत काफी अधिक है।

कठुआ में भल्ले वाला निकला आईएसआई का जासूस

- जम्मू-कश्मीर। कठुआ जिले में पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी के मामले में जांच एजेंसियों ने एक और युवक को हिरासत में लिया है. यह युवक लखनपुर में जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास यात्रियों को भल्ले बेचने का काम करता था. जांच में उसके पहले से हिरासत में लिए गए ट्रक चालक और सह चालक से संबंध सामने आने के बाद उसे पूछताछ के लिए पकड़ा गया है. जांच एजेंसियों के अनुसार, कठुआ के बरनोटी इलाके के रहने वाले 19 वर्षीय ट्रक चालक और 25 वर्षीय सह चालक को कथित तौर पर हनीट्रैप के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैंडलरों के संपर्क में लाया गया था.

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का इंतजार: 18 लाख तक एरियर संभव

नई दिल्ली। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है, जिसमें उनके वेतन, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है, इसकेउ बाद आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2026 से लागू करने की संभावना है।

हालांकि, यदि इन सिफारिशों को लागू करने में अपेक्षित समय से अधिक देरी होती है, तब कर्मचारियों को एक बड़ा वित्तीय लाभ एरियर के रूप में मिल सकता है।

अनुमान के अनुसार, यदि सिफारिशें लागू होने में 24 महीने की देरी होती है, तो लेवल-8 के एक केंद्रीय कर्मचारी को लगभग 18 लाख रुपये तक का एरियर मिल सकता है। इस गणना के पीछे का तर्क यह है कि यदि लेवल-8 के कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 47,600 रुपये है और आठवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो अनुमानित संशोधित मूल वेतन 1,22,332 रुपये होगा। इस तरह, मूल वेतन में मासिक वृद्धि लगभग 74,732 रुपये होगी। यदि यह वृद्धि 24 महीने बाद लागू होती है, तो केवल मूल वेतन के अंतर के आधार पर अनुमानित एरियर 74,732 रुपये को 24 महीने से गुणा करने पर लगभग 17,93,568 रुपये होगा। यह आंकड़ा एक उदाहरण मात्र है और वास्तविक एरियर की राशि लागू होने की तारीख और अन्य भत्तों में वृद्धि पर निर्भर करेगी।

आठवां वेतन आयोग इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन से जुड़े विभिन्न मामलों पर संबंधित हितधारकों के साथ गहन चर्चा कर रहा है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और चंडीगढ़ सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैठकें की हैं।

आयोग की योजना के अनुसार, आगामी दिनों में बेंगलुरु और मुंबई में भी हितधारकों से मुलाकात की जाएगी। हालांकि, अभी तक न तो केंद्र सरकार और न ही आठवें वेतन आयोग ने इन सिफारिशों को लागू करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित की है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, ताकि उनके वित्तीय भविष्य को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो सके।

एनआईए चाहती तो अमेरिकी नागरिक वैनडाइक को यूएस जाने से रोक लेती?

नई दिल्ली। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली की एक अदालत ने एक महीने के लिए अपने-अपने देशों में जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद वैनडाइक शुक्रवार शाम वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गया। हालांकि इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत जांच अभी जारी है, लेकिन अदालत के आदेश में स्पष्ट किया गया कि जांच पूरी करने के लिए इन आरोपियों की तत्काल भारत में भौतिक मौजूदगी जरूरी नहीं है। अदालत के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर इन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होना होगा और अपना पता, फोन नंबर व ईमेल जैसी संपर्क संबंधी जानकारी देनी होगी। वैनडाइक ने 21 अक्टूबर को भारत लौटने की फ्लाइट बुक की है। लोगों का कहना है कि एनआईए अदालत से अनुरोध तर्क रखती तो शायद वैनडाइक यूएस जाने से रोक लेती।

जांच एजेंसी के अनुसार, वैनडाइक और छह अन्य लोगों पर करीब तीन महीने तक म्यांमार स्थित जातीय सशस्त्र समूहों (जैसे चिन नेशनल फ्रंट और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी) के सदस्यों को ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन ऑपरेशन, ड्रोन असेंबली और जैमिंग तकनीक की ट्रेनिंग देने का आरोप है। एजेंसी का दावा है कि इन्हें म्यांमार के विद्रोही समूहों से लॉजिस्टिक मदद और फंड मिला था। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि चूंकि कथित गतिविधियां म्यांमार में हुईं, इसलिए वहां से सबूत हासिल किए बिना आतंकी साजिश को निर्णायक रूप से स्थापित करना और यूएपीए जांच पूरी करने की निश्चित समयसीमा तय करना एक चुनौती है।

इससे पहले, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) द्वारा हर आरोपी पर 5 .5 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर मामले का निपटारा कर दिया गया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें इस कानून के मामलों से डिस्चार्ज कर डिफॉल्ट बेल दे दी थी। तिहाड़ जेल से रिहाई और एफआरआरओ से एग्जिट परमिट मिलने के बाद इनकी वापसी की औपचारिकताएं पूरी की गईं। वैनडाइक को कोलकाता एयरपोर्ट और छह यूक्रेनी नागरिकों (हुर्बा पेट्रो, तारास स्लिवियाक, इवान सुखमानोव्स्की, मारियान स्टेफानकिव, मैक्सिम होंचारुक और विक्टर कामिन्स्की) को दिल्ली व लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इन पर बिना वैध दस्तावेजों के मिजोरम के रास्ते म्यांमार में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप था। इस बीच, सातों आरोपियों को भारत से बाहर जाने की अनुमति मिलने पर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इस रिहाई की परिस्थितियों और कथित अमेरिकी दबाव की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सरकार से तीखे सवाल किए हैं।

कांगो में सेना का विमान क्रैश

दो शीर्ष जनरलों समेत 16 लोगों की मौत

कांगो। लोकतांत्रिक गणराज्य में सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में मिलिट्री कोर्ट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुटोम्बो कटालायी टिएंडे और सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल एफोमी एकेन्गो ने आधिकारिक बयान जारी कर हादसे की पुष्टि की है।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, विमान दक्षिण-पश्चिमी शहर किकवित से राजधानी किंशासा लौट रहा था। उड़ान के दौरान विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद पायलट ने नियंत्रण खो दिया और विमान केंगे इलाके के पास एक प्लॉट में जा गिरा। टक्कर के बाद विमान में आग लग गई। विमान में दोनों जनरलों के अलावा प्रतिनिधिमंडल के 12 सदस्य और चालक दल के लोग सवार थे। हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा।

क्वांगो प्रांत के उप राज्यपाल रेमी साकी बोकिंडा के मुताबिक, तकनीकी खराबी के बाद पायलट ने केंगे में विमान उतारने की कोशिश की थी, लेकिन वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग की चपेट में आ गया। हादसे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। कांगो की सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन ट्रिफोन किन-कीये मुलुम्बा ने कहा कि दुर्घटना की वास्तविक वजह का पता लगाया जा रहा है। सेना ने विस्तृत तकनीकी जांच शुरू कर दी है। यह हादसा कांगो में जारी गंभीर सुरक्षा संकट के बीच हुआ है। देश की सेना पूर्वी हिस्से में रवांडा समर्थित ट23 विद्रोही गुट समेत कई सशस्त्र समूहों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चला रही है। हाल के महीनों में ट23 ने कई इलाकों में आक्रामक कार्रवाई करते हुए प्रमुख शहरों पर कब्जा किया है। ऐसे में शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौत को कांगो की सेना के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है।

खगोलविदों को मिला सबसे कम उम्र का ग्रह

वाशिंगटन। खगोलविदों ने अब तक सबसे कम उम्र का ग्रह खोजने का दावा किया है। इसकी उम्र दस लाख साल से भी कम बताई गई है। खगोलविदों ने इस नवजात ग्रह का नाम एलियास 2-24 बी रखा है। यह ग्रह अभी भी अपने युवा तारे के चारों ओर मौजूद गैस और धूल की विशाल डिस्क के भीतर तेजी से घूम रहा है! उसका आकार हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बराबर बताया गया है। यह ग्रह पृथ्वी से करीब 450 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस खोज से ग्रहों के निर्माण को लेकर मौजूदा वैज्ञानिक मॉडलों के सामने नए सवाल खड़े हुए हैं। अब तक जिन सबसे युवा ग्रहों की पहचान हुई थी, उनकी उम्र कम से कम करीब 50 लाख साल मानी जाती थी। इनमें पीडीएस 70 और विस्पिट 2 जैसे तारों की परिक्रमा कर रहे ग्रह शामिल हैं। इसके मुकाबले एलियास 2-24 बी की उम्र दस लाख साल से भी कम है।

भारतीय दूत ने साफ कहा-कश्मीर छोड़िए पीओके पर बात कीजिए...!

यूएन में पेटल गहलोत ने खूब सुनाई शहबाज को

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत करारा पलटवार किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आतंकवाद, सैन्य शासन, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार और जम्मू-कश्मीर के मुद्दों पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की ओर से बार-बार दोहराए जाने वाले झूठ कभी सच नहीं बन सकते। भारत ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान को हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर टिप्पणी करने के बजाय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के हालात पर ध्यान देना चाहिए,

जहां जनता लंबे समय से मनमानी हत्याओं, क्रूर हिंसा और बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने का सामना कर रही है।

भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बयान को बेतुका करार देते हुए दुनिया को 9/11 आतंकी हमले के संदर्भ की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि इस हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लदेन पाकिस्तान में सेना की प्रमुख अकादमी के बेहद करीब रह रहा था, जिसकी तारीफ आज उनका प्रतिनिधि कर रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने इसे फॉर्म 47 सरकार यानी चुनाव में धांधली कर बनाई गई व्यवस्था बताया।पाकिस्तान की राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने कहा कि जिस देश की राजधानी अपने ही नागरिकों के सुरक्षा के नाम पर किले में तब्दील की जा रही हो, उसे मानवाधिकारों पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस शासन को सेना का, सेना द्वारा और सेना के लिए शासन करार दिया। देश के 27वें संविधान संशोधन और सेना प्रमुख को आजीवन सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान में वास्तविक फैसले कौन करता है।

धार्मिक सहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बोलते हुए भारतीय दूत ने कहा कि कट्टरता और नफरत का लंबा इतिहास रखने वाली सरकार के उपदेश दुनिया को गुमराह नहीं कर सकते। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। भारत ने आतंकवाद को पाकिस्तान की पुरानी और सोची-समझी नीति बताया।

इटली के स्कूलों में विदेशी छात्रों की सीमा और बुर्का-नकाब पर बैन को मिली मंजूरी

रोम। इटली के स्कूलों को लेकर पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने क्लासरूम में विदेशी छात्रों की सीमा और बुर्का-नकाब पर बैन को मंजूरी दे दी है। मेलोनी ने कहा कि ये कदम छात्रों को बांटने के लिए नहीं बल्कि सभी को समान अवसर देने के लिए है। मेलोनी ने एक्स पर लिखा-आज हमने मंत्रिपरिषद में स्कूलों से जुड़े एक आदेश को मंजूरी दी। इसके तहत कक्षाओं में उन छात्रों की संख्या अधिकतम 30 फीसदी तक रखने की सीमा तय की

बराार शुरूआत का दें मौका

उन्होंने कहा कि ये ऐसे व्यावहारिक कदम है, जिनका मकसद लोगों को बांटना नहीं बल्कि उन्हें वास्तव में एक-दूसरे के साथ घुलने-मिलने में मदद करना है। इससे ऐसी अलग-थलग कक्षाएं बनने से बचा जा सकेगा, जहां एक खास समुदाय के छात्र ही ज्यादा हों और सभी छात्रों को बराबर मौके मिलेंगे। मेलोनी ने कहा कि हम आगे भी इसी दिशा में बढ़ना चाहते हैं यानी ऐसा स्कूल सिस्टम जो नियमों से समझौता किए बिना सभी को साथ लेकर चले, जिन छात्रों को ज्यादा मुश्किलें हैं उनकी मदद करे और हर छात्र को एक बराबर शुरूआत का मौका दे।

गई है, जिन्हें इतालवी भाषा ठीक से नहीं आती है। साथ ही उन्हें इतालवी भाषा सीखने में मदद के लिए सुविधाएं दी जाएंगी और स्कूलों में बुर्का पहनने की इजाजत नहीं होगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित नियम विशेष रूप से स्कूलों में पूरे चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर रोक से जुड़े हैं। बुर्का और नकाब में चेहरा ढका रहता है जबकि हिजाब में आम तौर पर सिर और गर्दन ढके होते हैं लेकिन चेहरा खुला रहता है। मेलोनी की घोषणा में बुर्का और नकाब का उल्लेख किया है। चेहरा ढकने पर बैन इटली के लिए बिल्कुल नया विषय नहीं है।

नवंबर में खत्म हो जाएगा ट्रंप का राज?

वॉशिंगटन। अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने दावा किया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा में फिर बहुमत हासिल कर सकती है। उनके मुताबिक, अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाएंगी। न्यूसम ने कहा कि नवंबर के चुनाव के बाद ट्रंप का राष्ट्रपति पद उस रूप में नहीं रहेगा, जैसा अभी है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रतिनिधि सभा में बहुमत बदलने से राष्ट्रपति का पद सीधे तौर पर कैसे प्रभावित होगा।

अमेरिकी व्यवस्था में राष्ट्रपति का कार्यकाल चुनाव के बीच में अपने आप समाप्त नहीं होता। लेकिन कांग्रेस के किसी एक या दोनों सदनों पर विपक्षी दल का नियंत्रण होने से राष्ट्रपति के विधायी एजेंडे और नीतियों पर राजनीतिक अड़चनें बढ़ सकती हैं। न्यूसम ने इसे ट्रंप प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के तौर पर पेश किया। उन्होंने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य पर टिप्पणी की। न्यूसम ने कहा कि अगला राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से हो सकता है। उन्होंने रिपब्लिकन नेताओं मार्को रुबियो और जेडी वेंस का भी उल्लेख किया, जिन्हें भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण चेहरों के तौर पर देखा जाता है।

डेमोक्रेटिक सांसद एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के संभावित राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के सवाल पर न्यूसम ने कहा कि वह पार्टी की उम्मीदवार बन सकती हैं। उन्होंने इस धारणा को खारिज किया कि महिला उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीतना संभव नहीं है। हालांकि, न्यूसम ने खुद 2028 की दौड़ को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की। न्यूसम ने जलवायु नीति को भी आर्थिक मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चर्चा केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि किराने के सामान की कीमत, घर का बीमा, कर्ज और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों से भी इसका संबंध है। उन्होंने जंगलों में आग और तटीय इलाकों में बढ़ते जोखिमों का जिक्र करते हुए कहा कि जलवायु नीतियों का असर आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। कैलिफोर्निया को उदाहरण बताते हुए न्यूसम ने दावा किया कि वहां आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई साथ-साथ आगे बढ़े हैं।

ह्यूमनॉइड रोबोट के जरिये चीन की युद्ध का तरीका बदलने की तैयारी

बीजिंग। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोटों को भविष्य में सैन्य प्रशिक्षण और युद्ध संबंधी भूमिकाओं में इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और स्वायत्त हथियारों के बाद अब ह्यूमनॉइड रोबोट सैन्य तकनीक की अगली बड़ी कड़ी बनते दिखाई दे रहे हैं। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े आधिकारिक अखबार में शोधकर्ताओं से उन्नत रोबोटों को प्रयोगशालाओं से बाहर निकालकर सैन्य प्रशिक्षण में इस्तेमाल करने की दिशा में तेजी लाने की अपील की गई है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि चीन ने रोबोट सैनिकों की कोई तैयार लड़ाकू सेना तैनात कर दी है।

चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट विकास को हाल में आयोजित वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स जैसे आयोजनों से भी गति मिली है। इन प्रतियोगिताओं में रोबोटों की दौड़, चलने, संतुलन बनाने और अलग-अलग शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता प्रदर्शित की गई। टियांगगोंग अल्ट्रा नाम के एक ह्यूमनॉइड रोबोट द्वारा 100 मीटर की दौड़ 8 .64 सेकंड में पूरी करने का दावा भी चर्चा में रहा। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कुछ रोबोटों के गिरने और असंतुलित होने के वीडियो भी सामने आए, लेकिन शोधकर्ताओं के लिए यह तकनीकी विकास का हिस्सा है। सैन्य क्षेत्र में ह्यूमनॉइड रोबोट का संभावित फायदा उन स्थानों पर हो सकता है जिन्हें मूल रूप से इंसानों के लिए बनाया गया है। सीढ़ियां चढ़ना, दरवाजे खोलना, संकरी जगहों में जाना या किसी वाहन के भीतर इंसान की तरह पहुंचना ऐसे काम हैं, जिनमें मानव आकार की मशीनों को डिजाइन किया जा सकता है।

इसके अलावा खतरनाक इमारतों की जांच, विस्फोटक या संदिग्ध वस्तुओं वाले क्षेत्रों की निगरानी और आपदा प्रभावित स्थानों में बचाव कार्य जैसे गैर-लड़ाकू उपयोग भी संभव हैं। इन रोबोटों की क्षमता बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सॉफ्टवेयर अहम भूमिका निभा रहे हैं। रीइन्फोर्समेंट लर्निंग जैसी तकनीकों के जरिए मशीनों को सिमुलेशन वातावरण में अलग-अलग परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए रोबोट संतुलन बिगड़ने पर खुद को संभालना, बाधाओं के बीच रास्ता बनाना और बदलते वातावरण के अनुसार अपनी गतिविधियां समायोजित करना सीख सकता है।

नितिन गडकरी से भोपाल को 2471 करोड़ का मेगा गिफ्ट

मिसरोद से अयोध्या बायपास तक बनेगा 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर

भोपाल। राजधानी में ट्रैफिक के दबाव को कम करने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिसरोद से एम्प्री, चेतक ब्रिज और रत्नागिरी होते हुए अयोध्या बायपास जंक्शन तक 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर अपनी सहमति दे दी है। 2,471 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर तीन अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में केंद्र की 'वन टाइम इंप्रूवमेंट स्कीम' के तहत इसे हरी झंडी दी गई। वर्ष 2026-27 की योजना के तहत प्रदेश की 47 सड़कों के कायाकल्प पर कुल 4,293 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इन 5 महा-प्रोजेक्ट्स को भी जल्द मिलेगी रफ्तार

मध्य प्रदेश सरकार ने कनेक्टिविटी को नए आयाम देने के लिए केंद्र से 5 अन्य बड़े कॉरिडोर को भी शीघ्र हरी झंडी देने का अनुरोध किया है। इसमें पहला सतना-चित्रकूट 4-लेन है। 4,550 करोड़ रुपये की लागत वाले 77 किमी लंबे इस मार्ग से चित्रकूट धाम की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

मरम्मत पूरी होने तक शाहपुरा आरओबी टोल पर पूरी तरह रोक

फरवरी महीने में क्षतिग्रस्त हुए शाहपुरा फ्लाई-ओवर की अप्रोच रोड को लेकर केंद्रीय मंत्री ने राहत भरा फैसला लिया है। जब तक सड़क का पुनर्निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक के लिए टोल वसूली तुरंत प्रभाव से स्थगित करने पर सहमति बन गई है। 30 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही काम शुरू होगा और पूर्ण यातायात बहाल होने के बाद ही टोल प्रक्रिया दोबारा लागू की जाएगी।

आलीराजपुर में बड़ी वारदात, पत्नी ने पति को मारकर जलाई लाश, बचे हिस्सों को घर के पीछे रेत में गाड़ा

आलीराजपुर। उदयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ताती-अंबा के पुजारा फलिया में 15 दिन से लापता एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रामा वाकला (50) का शव उसके ही घर के पीछे बने कमरे में रेत के नीचे दबा मिला। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी नाहजुबाई (47) ने पूछताछ में पति की हत्या करने की बात स्वीकार की है।

पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को मृतक के बेटे राहुल ने सूचना दी कि उसके पिता करीब 15 दिनों से लापता हैं। पिता के अचानक गायब होने से उसे अनहोनी की आशंका हुई। गुजरात के राजकोट में मजदूरी कर रहे राहुल के घर लौटने के बाद उसने अपनी मां से पिता के बारे में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान संदेह गहराने पर घर की तलाशी ली गई। इसी दौरान घर के पीछे स्थित कमरे में रेत के नीचे दबे मानव अवशेष दिखाई दिए। सूचना मिलते ही उदयगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची।

बैतूल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस देखने गई 17 वर्षीय छात्रा की अचानक मौत

बैतूल। जेएच कॉलेज परिसर में शुक्रवार रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान 17 वर्षीय छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। छात्रा अपनी सहेलियों के साथ गणेश प्रतिमा के विसर्जन का जुलूस देखने गई थी।

इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रतीक्षा पिता नितेश वर्मा (17), निवासी सुहागपुर ढाना, थाना शाहपुर बैतूल के विकास नगर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह जेएच कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। एसडीओपी अन्नपूर्णा सिरसाम के अनुसार शुक्रवार रात करीब 9 से 10 बजे के बीच गणेश प्रतिमा विसर्जन का जुलूस कॉलेज परिसर से निकाला जा रहा था। जुलूस देखने के लिए प्रतीक्षा अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची थी। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश होकर गिर गई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका के चाचा मोहन दास ने कार्यक्रम के दौरान बज रहे तेज डीजे साउंड को छात्रा की तबीयत बिगड़ने और मौत की वजह बताया है।

शान्तनु मोइत्रा को मिलेगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान

28 सितंबर को इंदौर में अलंकरण समारोह, सचेत-परम्परा की संगीत संध्या

इंदौर। मध्यप्रदेश शासन का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान-2026 इस वर्ष संगीत निर्देशन के लिए प्रसिद्ध संगीतकार शान्तनु मोइत्रा को प्रदान किया जाएगा। उन्हें 28 सितंबर को इंदौर के लता मंगेशकर सभागार में आयोजित अलंकरण समारोह में पांच लाख रुपये की कर-मुक्त राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा।

मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन, इंदौर के सहयोग से 27 और 28 सितंबर को लता मंगेशकर सभागार, वीआइपी परस्पर नगर में शाम सात बजे से दो दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। दोनों दिन कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। आयोजन के पहले दिन 27 सितंबर को ह्यअमर लता हमारी लताङ्क्ष्ह शीर्षक से संगीत संध्या होगी। इसमें इंदौर के गायक कलाकार अभय आहूजा, विवेक भारद्वाज, संजोत बरोट, पद्मा शुक्ला, सुषमा राव, सिद्धार्थ दुबे, वैशाली चौहान, मुस्कान चौहान, सौम्या सिन्हा और दीपिका पुरोहित गीत-संगीत की प्रस्तुति देंगे।

परिणीता से 12वीं फेल तक संगीत का सफर

22 जनवरी 1968 को लखनऊ में जन्मे मोइत्रा ने विज्ञापन जगत से संगीत के क्षेत्र में कदम रखा और बाद में हिंदी सिनेमा में संगीत निर्देशक तथा बैकग्राउंड स्कोर कम्पोजर के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने परिणीता, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, लगे रहो मुन्नाभाई, 3 इडियट्स, मद्रास कैफे, पीकू, अक्टूबर और 12वीं फेल जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया है। तेलुगु फिल्म ना बंगारू तल्लि के लिए उन्हें 2014 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था।

28 सितंबर को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित होगा। इसके बाद लोकप्रिय गायक जोड़ी सचेत-परम्परा की संगीत संध्या होगी।

1984 में स्थापित हुआ था सम्मान

सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने 1984 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना की थी। यह सम्मान बारी-बारी से संगीत रचना और गायन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब तक 42 विभूतियों को इस सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। पिछले समारोह में वर्ष 2024 के संगीत निर्देशन के लिए शंकर-एहसान-लॉय तथा वर्ष 2025 के पार्श्व गायन के लिए सोनू निगम को सम्मानित किया गया था। संस्कृति विभाग के अनुसार, इंदौर में जन्मीं लता मंगेशकर की स्मृति में आयोजित यह समारोह उनकी संगीत विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयास का हिस्सा है। मध्यप्रदेश शासन ने महान विभूतियों की स्मृति में 20 से अधिक सम्मान स्थापित किए हैं।

दो ट्रकों की टक्कर के बाद लगा लंबा जाम

दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर गड्ढों ने फिर बिगाड़ा सफर

दमोह। दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर सिंग्रामपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सड़क की बदहाली एक बार फिर वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन गई। शनिवार सुबह दानीताल और धबालेन के बीच दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब सात घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। हादसे की सूचना मिलने पर सिंग्रामपुर चौकी प्रभारी विकास सिंह चौहान पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों के सड़क पर फंसे होने के कारण यातायात बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मशीन की मदद से दोनों ट्रकों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद जाम खुल सका और वाहनों की आवाजाही पुनः शुरू कराई गई।

सुबह करीब 5 बजे हुई भिड़ंत

सिंग्रामपुर चौकी प्रभारी विकास सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे सतघटिया के जंगल क्षेत्र में दो ट्रकों के आमने-सामने भिड़ने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए मशीन की मदद ली गई। काफी प्रयास के बाद हाईवे पर यातायात को सुचारू कराया गया।

जर्जर सड़क और गड्ढों से बढ़ रहा हादसों का खतरा

दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे के सिंग्रामपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्से में सड़क की स्थिति को लेकर वाहन चालक लंबे समय से परेशानी जता रहे हैं। सड़क पर जगह-जगह बड़े और गहरे गड्ढे बने हुए हैं। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना वाहन चालकों के लिए मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों और नियमित वाहन चालकों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खासकर रात और बारिश के समय स्थिति और अधिक जोखिम भरी हो जाती है। वाहन चालक गड्ढों से बचने के लिए अचानक दिशा बदलते हैं, जिससे आमने-सामने से आने वाले वाहनों के बीच टक्कर का खतरा बढ़ जाता है।

दो ट्रकों की भिड़ंत के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई। दोनों ओर ट्रक, बस और अन्य छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे यात्रियों और वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। पुलिस द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद यातायात व्यवस्था बहाल हो सकी।

उज्जैन के माधव कॉलेज में गणेश प्रतिमा चोरी का आरोप

छात्रों ने प्रिंसिपल की टेबल पर लड्डू रख उतारी आरती

उज्जैन। धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित 'पीएम एक्सीलेंस' शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में गणेशोत्सव पर्व के दौरान उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब कॉलेज परिसर से स्थापित गणेश जी की प्रतिमा रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई। इस घटना से आक्रोशित छात्र सीधे प्राचार्य डॉ. कल्पना सिंह के कक्ष में घुस आए और एक अनोखा व तीखा प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्राचार्य को 'गणेश' मानकर की आरती और चढ़ाया भोग

छात्रों ने प्राचार्य की मेज पर सैकड़ों लड्डुओं से भरी परात रख दी। विरोध दर्ज कराते हुए छात्रों ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय प्रशासन की शह पर यह सब हो रहा है, इसलिए वे प्राचार्य को ही गणेश जी का प्रतीक मानकर उनके सामने लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं और आरती गा रहे हैं। इस दौरान प्राचार्य कक्ष में काफी देर तक गहमागहमी और नोकझोंक का माहौल बना रहा।

पक्षपात और राजनीति का आरोप

प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है के महाविद्यालय प्रशासन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के प्रति रणनीतिक समर्थन दिखा रहा है और आम विद्यार्थियों के साथ भेदभाव कर रहा है। छात्रों ने कहा कि वे वर्षों से मिल-जुलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में गणेशोत्सव मनाते आ रहे हैं। परंतु इस बार रणनीति के तहत आम छात्रों को मुख्य धार्मिक आयोजन व आरती से दूर रखने का प्रयास किया गया और बाद में प्रतिमा को ही गायब करा दिया गया।

कालिख की डिब्बी रखी, इस्तीफे की मांग की

छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि प्रतिमा गायब होने के मामले में कोई ठोस जवाब नहीं मिलता तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने मेज पर एक काली स्याही (कालिख) की डिब्बी रखते हुए कहा कि पक्षपात करने वाले अधिकारी या तो दोषियों पर कार्रवाई करें या फिर स्वयं अपने चेहरे पर कालिख पोत लें। इसके साथ ही छात्रों ने कॉलेज को निष्पक्ष रूप से चलाने में असफलता का हवाला देते हुए प्राचार्य से नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने (इस्तीफे) की मांग की।

प्राचार्य का रुख, जांच के बाद होगी कार्रवाई

दूसरी ओर, प्राचार्य डा. सिंह ने कक्ष में बिना अनुमति दाखिल होने, वीडियोग्राफी करने और अमर्यादित रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था में नियमों का पालन आवश्यक है। प्राचार्य ने छात्रों से शांत रहने और अनुशासन समिति को लिखित शिकायत देने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और घटना में शामिल तथा अनुशासनहीनता करने वाले आरोपित छात्रों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नर्सिंग कॉलेजों के पदाधिकारियों एवं छात्र-छात्राओं ने किया स्वागत

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल का कटनी ज़िले के अल्प प्रवास में जिले के विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भेंट कर आत्मीय स्वागत किया तथा नर्सिंग विद्यार्थियों के लंबित परीक्षा परिणाम जारी कराने की पहल के लिए उनका आभार व्यक्त किया। जिले के एमजीएम कॉलेज/स्कूल नर्सिंग कॉलेज, श्री साईनाथ कॉलेज एवं विजडम नर्सिंग कॉलेज, कटनी के पदाधिकारियों सहित नर्सिंग कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल का स्वागत किया।

प्रदेश में तेजी से हो रहा हैं सड़क परियोजनाओं का क्रियान्वयन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की पहल से प्रदेश में सड़क परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो रहा हैं। इससे औद्योगिक गतिविधियों के साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी को प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं और भविष्य के सड़क विस्तार योजनाओं की जानकारी भी दीं।

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हर प्रोजेक्ट का डिजाइन सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी तकनीकी मानकों के अनुरूप हों। ऐसे स्थानों पर जहाँ क्षेत्रीय निवासियों को हो रही कठिनाईयों के कारण, सड़क परियोजनाएं लम्बित हो रही है, वहां परस्पर संवाद और समन्वय से समाधान निकाला जाए। भूमि अधिग्रहण और वन स्वीकृति के प्रकरणों में राज्य सरकार के अधिकारी केन्द्रीय मंत्रालयों से परस्पर सम्पर्क में रहें। किसी भी स्थिति में परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब न हों। बैठक में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल उपस्थित थे। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का बटेश्वर (उ.प्र.) से विशेष संबंध रहा है। अटल एक्सप्रेस-वे का निर्माण बटेश्वर तक किया जाएगा। उन्होंने सिंहस्थ : 2028 के दृष्टिगत उज्जैन को जोड़ने वाले सभी मार्गों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने जबलपुर के शहपुरा आर.ओ.बी. के क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित आवागमन के दृष्टिगत नागरिकों की परेशानी को देखते हुए शहपुरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली स्थगित करने के निर्देश दिए।

7.5 लाख कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, दीवाली से पहले बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

भोपाल। मध्य प्रदेश के लगभग साढ़े सात लाख शासकीय सेवकों के लिए आगामी त्योहारी सीजन खुशियों भरा साबित होने जा रहा है।

प्रदेश सरकार इस बार दीवाली के अवसर पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, राज्य शासन 15 अक्टूबर के बाद इस फैसले का आधिकारिक ऐलान कर सकता है, ताकि नवंबर महीने के वेतन में बढ़ा हुआ भत्ता जोड़कर दिया जा सके।

वर्तमान में 58 प्रतिशत की दर से मिल रहा है डीए

वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 58% की दर से डीए मिल रहा है, जो इस 2 प्रतिशत के इजाफे के साथ बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों का यह 2 प्रतिशत डीए 1 जनवरी से लंबित है। इस बढ़ोतरी को लागू करने से राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 82 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। इसके अलावा, जनवरी से अक्टूबर तक का 10 महीने का एरियर देने पर सरकार को कुल 820 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान करना पड़ेगा। एरियर का भुगतान एकमुश्त होने से कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।

किस वर्ग के वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी?

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीः यदि मूल वेतन लगभग 30,000 रुपये है, तो प्रतिमाह करीब 600 रुपये का इजाफा होगा।

तृतीय श्रेणी कर्मचारीः 40,000 रुपये से 50,000 रुपये तक बेसिक पे वाले कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 800 रुपये से 1,000 रुपये तक बढ़ जाएगी।

अधिकारी वर्गः 70,000 रुपये से 1,00,000 रुपये या उससे अधिक बेसिक पे वाले अफसरों की मासिक आय में 1,400 रुपये से 2,000 रुपये तक की वृद्धि होगी।

सुपर क्लास-1 अधिकारीः इनके वेतन में प्रति माह 3,500 रुपये से 4,000 रुपये तक का इजाफा देखा जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर भी टिकी हैं निगाहें

राज्य के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों में भी महंगाई भत्ते को लेकर सुगबुगाहट तेज है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई से लंबित है, जिसमें लगभग 3 फीसदी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ ने वित्त मंत्रालय से जल्द घोषणा करने का अनुरोध किया है। वहीं, मध्य प्रदेश के सरकारी सेवक अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में जारी होने वाले आधिकारिक आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अभी संन्यास नहीं लेंगे रोनाल्डो, पुर्तगाल के लिए खेलते रहेंगे

लिस्बन। फीफ विश्वकप फुटबॉल में पुर्तगाल टीम के खराब प्रदर्शन के बाद से ही अटकलें लगायी जा रही थीं कि टीम के कप्तान और स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब किसी भी समय संन्यास ले सकते हैं पर रोनाल्डो ने इससे इंकार किया है।

इस फुटबॉलर का कहना है कि अभी उनका संन्यास लेने का कोई ईरादा नहीं है। साथ ही कहा कि वह तब तक खेलते रहेंगे जब तक मैदान पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रोनाल्डो ने हालांकि माना है कि विश्व कप में टीम की हार के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के बारे में गंभीरता से सोचा था, पर अब उनका पूरा ध्यान आगामी मुकाबलों में पुर्तगाल को जीत दिलाने और टीम के लक्ष्यों को हासिल करने पर केंद्रित है।रोनाल्डो ने बताया कि विश्व कप के अंतिम-16 में स्पेन के खिलाफ मिली हार के बाद उनके मन में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को खत्म करने का विचार आया था। उन्होंने कहा, हां, मैंने ऐसा सोचा था। मैं हमेशा अपने फैसलों, अपने भविष्य और वर्तमान

के बारे में सोचता रहता हूं। हालांकि, अब उन्होंने इस पर अंतिम निर्णय ले लिया है और अपने देश के लिए खेलना जारी रखने का संकल्प लिया है।

इस 39 वर्षीय दिग्गज खिलाड़ी ने बताया कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में देश के फुटबॉल संघ के अध्यक्ष और अपने पूर्व क्लब अल-नासर के कोच जॉर्ज जीसस से विस्तार से बातचीत के बाद फैसला किया है। जीसस, जिन्होंने हाल ही में मई में अल-नासर को सऊदी लीग का प्रतिष्ठित खिताब दिलाया था और रोनाल्डो की क्षमताओं से भली-भांति परिचित हैं, ने भी इस चर्चा में भाग लिया। रोनाल्डो ने कहा, मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि मैं राष्ट्रीय टीम की मदद कर सकता हूं और उसे उसके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा सकता हूं। मैं तब ही संन्यास लूंगा, जब मुझे यह महसूस होगा कि मैं टीम के लिए अब कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हूं।अपने करियर में 1,000 गोल पूरे करने के बेहद करीब पहुंच चुके रोनाल्डो ने आगे कहा कि भले ही टीम में एक नई और युवा पीढ़ी का उदय हो रहा है, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैदान पर उतरकर अपना शत-प्रतिशत देना, गोल दागना और अपनी टीम को मैच जिताने में हर संभव मदद करना है। वह 2025 में नेशंस लीग का खिताब दिलाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं।

एशियाई खेलों में वैभव को अंतिम ग्यारह में जगह मिलना तय : कैफ

मुम्बई। भारतीय टीम 28 सितंबर से एशियाई खेलों में अपना अभियान शुरू करेगी। भारतीय टीम को रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह दी गयी हे। वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि इन खेलों में भारतीय टीम उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को जरुर अवसर देगी। इसके लिए भले ही उसे तिलका वर्मा या शिवम दूबे के बाहर बिठाना पड़े। कैफ ने टीम संयोजन को लेकर दिये बयान में कहा है युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लंबे समय तक अंतिम ग्यारह से बाहर नहीं रखा जा सकता। साथ ही कहा कि उन्हें टीम में जगह देने के लिए तिलक या शिवम जैसे खिलाड़ियों को भी बाहर किया जा सकता है। कैफ के अनुसार वैभव ने अब तक अपने करियर में जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए टीम प्रबंधन के लिए उन्हें लंबे समय तक बाहर रखना असंभव होगा।

कैफ के अनुसार, टीम प्रबंधन का ध्यान इस बात पर नहीं होना

चाहिए कि वैभव सूर्यवंशी के लिए अंतिम इलेवन में जगह है या नहीं, बल्कि इस पर होना चाहिए कि उन्हें टीम में कैसे फिट किया जाए। कैफ का मानना है कि इस बल्लेबाज को अंतिम ग्यारह में शामिल करने से भारतीय टीम को ही फायदा होगा। उन्होंने अगले छह महीनों में एक ऐसे संयोजनप की संभावना जताई जिसमें वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा तीनों एक साथ भारतीय टीम का हिस्सा हों।

कैफ ने कहा कि अगर टीम प्रबंधन इस उभरते हुए खिलाड़ी को अंतिम ग्यारह में शामिल करना चाहता है, तो तिलक या शिवम में से किसी एक की जगह पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि तिलक भले ही टीम के उप-कप्तान हों, भारतीय क्रिकेट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि उप-कप्तान को अंतिम ग्याहर से बाहर नहीं किया जा सकता। टीम की जरूरत के हिसाब से यह फैसला लिया जा सकता है। वहीं, शिवम दुबे को लेकर कैफ का कहना था कि उनका उपयोग मुख्य रूप से बल्लेबाज के तौर पर हो रहा है, उनसे ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराई जा रही और फील्डिंग भी उनकी कमजोर है। ऐसे में वैभव के लिए जगह बनाने की स्थिति में शिवम को बाहर बैठना पड़ सकता है।

अगले माह अजरबैजान में खेला जाएगा पहला फीफा अंडर-15 विश्व कप फुटबॉल

बाकू। विश्व फुटबॉल की उभरती हुई प्रतिभाएं अब अजरबैजान के बाकू में अगले माह होने होने वाले पहले फीफा अंडर-15 विश्व कप और फेस्टिवल अजरबैजान 2026 में खेलती दिखेंगी। इसमें कुल 191 टीमें भाग लेंगी। भारतीय टीम भी इसमें भाग लेगी। भारतीय टीम ग्रुप के में रखा गया है।इसमें भारतीय टीम 24 से 26 अक्टूबर के बीच लाओस, कैमरून, ग्रेनाडा, बहरीन और सेनेगल से पांच मैच खेलेगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अनुसार इस टूर्नामेंट से युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।

एशियाई खेलों में भारतीय टीम को सतर्क रहना होगा : गावस्कर

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि एशियाई खेलों में भारतीय टीम को काफी सावधान रहना होगा।

गावस्कर के अनुसार टीम को एक ऐसे अलग तरीके के माहौल का सामना करना पड़ेगा जो आमतौर पर क्रिकेट खेलने वाले देशों में नहीं देखा जाता। भारतीय टीम अपना पहला मैच 28 सितंबर को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेलेगी, जिसमें क्रिकेट और बेसबॉल के मैच खेले जाते हैं। गावस्कर ने कहा कि यह कोई आम क्रिकेट खेलने वाला देश नहीं है, जिससे माहौल और दर्शकों की संख्या में बड़ा अंतर आ सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शायद यहाँ का माहौल वैसा नहीं होगा जैसा आमतौर पर क्रिकेट खेलने वाले देशों में देखने को मिलता है। इसलिए हालात अलग हो सकते हैं और दर्शकों की संख्या भी भारत के मैचों के मुकाबले काफी कम रहेगी। पिच के बारे में भी सही अनुमान लगाना कठिन मुश्किल है। हालांकि, उन्होंने क्रिकेट की इसी अनूठी चुनौती को इसकी खूबसूरती बताया। गावस्कर ने कहा, क्रिकेट की सुंदरता यही है कि जब क्रिकेटर अपने शहरों में क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो वे मैदानों पर खेलते हैं, ड्रेसिंग

रूम सिर्फ. टेंट होते हैं, और आउटफील्ड हमेशा सबसे अच्छे नहीं होते। मुझे लगता है कि यही चुनौती है, और उस चुनौती को पार करके जीतना और भी खास होगा।

गावस्कर ने भारतीय टीम के अपने शीर्ष क्रिकेटरों के साथ इस इवेंट में उतरने के फैसले की तारीफ की।

भारतीय बल्लेबाजी को बेहतरनी बताते हुए उन्होंने कहा कि उसके निचले क्रम के बल्लेबाज भी तेजी से रन बना सकते हैं।। वहीं मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल करने को भी उन्होंने एक अच्छा विचार बताया, जिससे उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले कुछ अभ्यास मिल जाएगा। कप्तान श्रेयस अय्यर के अनुभव पर भी उन्होंने जोर दिया, कहा कि आईपीएल में उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं होना चाहिए। गावस्कर ने यह भी जोड़ा कि देश की कप्तानी करने का सम्मान और सौभाग्य हर कप्तान को मिलता है, इसलिए एशियाई खेलों में अय्यर पर कोई खास दबाव नहीं होगा। हालांकि, गावस्कर ने आगाह किया कि यह एक टी20 टूनामेंट है, इसलिए चुनौती कड़ी होगी। उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान को खतरनाक टीमें बताया, जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। गावस्कर ने नेपाल की भी तारीफ की, जो हाल ही में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और जिसने टी20 विश्व कप में इंग्लैंड जैसी टीमों को हैरान कर दिया था।

महिला क्रिकेटर फातिमा अब बाबर आजम से भी आगे निकली : वसीम

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद वसीम ने महिला क्रिकेट टीम के कप्तान फातिमा सना की जमकर तारीफ की है। वसीम ने कहा कि आज के समय में फातिमा पुरुष टीम के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम से भी बेहतर है। साथ ही कहा कि अपने प्रदर्शन से उसने लोकप्रियता में बाकर को भी पीछे छोड़ दिया है।

महिला टीम के कोच रहे वसीम ने कहा कि अगर क्रिकेट को गहराई से समझने वाले और जानकार दर्शकों के बीच फातिमा और बाबर की तुलना की जाए, तो फातिमा कहीं आगे खड़ी नजर आती हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या बाबर पुरुष टीम में फातिमा के समकक्ष हैं, तो वसीम ने बिना किसी झिझक के फातिमा को इन सबसे ऊपर रखा। उन्होंने इस बात पर गर्व और दुख दोनों जताया कि फातिमा कई बार असाधारण प्रदर्शन करने के बावजूद हारने वाली टीम का हिस्सा बन जाती हैं। वसीम ने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक टीवी एंकर को फातिमा को पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर बताते हुए सुना था, और वह इस बात से पूरी तरह सहमत हैं।

मोहम्मद वसीम के अनुसार, लोकप्रियता केवल नाम या पहचान से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर और प्रभावी प्रदर्शन से बनती है। उन्होंने कहा कि फातिमा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, और अब जब पुरुष और महिला क्रिकेटरों को एक साथ देखा जा रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी उनकी खूब तारीफ होती है। वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान के पुरुष क्रिकेट के कई बड़े नामों को मौजूदा समय में इस तरह की लगातार प्रशंसा नहीं मिल रही है, जिसके पीछे उनका मौजूदा प्रदर्शन भी एक बड़ी वजह है।

प्रभावी खिलाड़ियों में से एक रही है

गौरतलब है कि फातिमा सना पाकिस्तान महिला टीम की कप्तान हैं और उन्हें दुनिया की बेहतरीन महिला हरफनमौला खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है। उन्होंने अब तक 134 एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 157 विकेट अपने नाम किए हैं, जबकि निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 1500 से ज्यादा रन भी बनाए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान महिला टीम को बड़े टूर्नामेंटों में भले ही लगातार सफलता न मिली हो, लेकिन फातिमा अपने गेंद और बल्ले दोनों से कई मौकों पर टीम के लिए सबसे प्रभावी खिलाड़ियों में से एक रही हैं।

उठ रहे हैं सवाल

मौजूदा जानकारी के अनुसार, फातिमा की यही निरंतरता उन्हें पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ियों से एक अलग पहचान देती है। दूसरी ओर, बाबर आजम एक बार फिर दबाव में हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में पाकिस्तान को 0-3 से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद बाबर की कप्तानी और उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं।

कारोबार

बैंक हड़ताल के बीच राहत की खबर: 28-30 सितंबर को खुले रहेंगे देशभर के सहकारी बैंक; जारी रहेंगी सभी सेवाएं

नई दिल्ली। 28 से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल के बीच सहकारी बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है।

सहकारी बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे और सामान्य रूप से कामकाज जारी रखने की बात कही गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल का प्रमुख मुद्दा बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करने की मांग है। हालांकि, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख संस्थाओं ने स्पष्ट किया है कि सहकारी बैंक प्रस्तावित हड़ताल में शामिल नहीं हैं। ऐसे में इन बैंकों की शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं जारी रहने की उम्मीद है।

सहकारी बैंकों में कौन-कौन सी सेवाएं मिलेंगी?

सहकारी बैंकों के ग्राहकों को शाखा स्तर पर उपलब्ध सामान्य सेवाएं मिलती रहेंगी। इनमें पैसे जमा करना, निकासी, रेमिटेंस और अन्य बैंकिंग लेनदेन शामिल हैं। हालांकि, किसी विशेष बैंक में किसी सेवा की उपलब्धता उसके स्थानीय परिचालन और व्यवस्था पर निर्भर कर सकती है। इसलिए ऐसे लेनदेन जिनमें शाखा स्तर पर प्रक्रिया पूरी करनी होती है, उनके लिए ग्राहकों

को संबंधित बैंक या शाखा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है।

किसानों और छोटे कारोबारियों को भी राहत

सहकारी बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग और ऋण सेवाओं का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनके जरिए किसानों, ग्रामीण परिवारों, छोटे कारोबारियों, व्यापारियों और उद्यमियों को बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं। हड़ताल के दौरान पात्र किसानों और सदस्यों के लिए कृषि एवं ग्रामीण ऋण से जुड़ी सेवाएं भी संबंधित बैंक की व्यवस्था के अनुसार जारी रहने की उम्मीद है। सहकारी बैंकों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली डिजिटल सेवाएं भी जारी रहने की उम्मीद है। इनमें अळट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और वढकजैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता संबंधित बैंक के सिस्टम और परिचालन व्यवस्था पर निर्भर करेगी। इसलिए किसी जरूरी डिजिटल या बैंकिंग लेनदेन से पहले ग्राहक अपने बैंक की जानकारी जरूर जांच लें।

कितने सहकारी बैंक हैं?

भारत में सहकारी बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार काफी बड़ा है। इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। ये बैंक शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भी ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यही वजह है कि हड़ताल के दौरान इनके सामान्य रूप से खुले रहने की जानकारी ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

अगर आपको 28 से 30 सितंबर के बीच बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो अपने सहकारी बैंक की शाखा से पहले संपर्क कर लें। खासकर ऐसे काम जिनमें दस्तावेजों की जांच या शाखा स्तर पर प्रक्रिया जरूरी हो सकती है, उन्हें लेकर पहले पुष्टि करना बेहतर रहेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी प्रस्तावित बैंक हड़ताल के मद्देनजर बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान कम करने के लिए कदम उठाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 27 सितंबर, रविवार को भी सामान्य रूप से खुले रखने की घोषणा की गई है।

आईआरडीएआई के प्रस्ताव से पीबी फिनटेक में भूचाल: दो दिन में 40% टूटा शेयर; कंपनी के 31,400 करोड़ डूबे

मुम्बई। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म पॉलिसीबाजार की मूल कंपनी पीबी फिनटेक पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। बीमा नियामक आईआरडीएआई (इरडा) की ओर से बीमा वितरण के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव देने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है। शुक्रवार को भी पीबी फिनटेक का शेयर 3.68% कमजोर हुआ। इससे एक दिन पहले कंपनी का शेयर करीब 36% टूटा था। दो दिन में शेयर करीब 40% टूट चुका है। शुक्रवार को बीएसई पर पीबी फिनटेक का शेयर 1,165.50 रुपये पर बंद हुआ। 24 सितंबर को शेयर 1,896.45 रुपये के स्तर से टूटा था।

31,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की बाजार पूंजी साफ

इस भूचाल के कारण कंपनी की बाजार पूंजी 31,400 करोड़ रुपये से ज्यादा साफ हो चुकी है। कंपनी के सह-संस्थापक याशिश दहिया ने माना है कि यदि ये नियम लागू होते हैं, तो जनरल इंश्योरेंस से मिलने वाला राजस्व मौजूदा स्तर से एक-तिहाई से 40% तक कम हो सकता है। हालांकि, कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 में तुरंत किसी बड़े असर की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगला वित्त वर्ष चुनौतियों भरा हो सकता है। दहिया ने संकेत दिए हैं कि यदि डिस्ट्रीब्यूटरों को उनके काम का उचित रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो कंपनी भविष्य में खुद के बीमा उत्पाद बनाने के क्षेत्र में उतरने पर विचार कर सकती है। कंपनी अपने डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड पर होने वाले खर्च, सेल्स और कस्टमर सपोर्ट की समीक्षा कर रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर छंटनी की कोई योजना नहीं है।

बाजार से 1.20 लाख करोड़ कम कर्ज लेगी सरकार; दूसरी छमाही में जुटाएगी 7.86 लाख करोड़, तैयार किया नया प्लान

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में बाजार से लिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य घटा दिया है। सरकार अब पूरे वित्त वर्ष में 15.99 लाख करोड़ रुपये की बाजार उधारी करेगी। बजट में इसके लिए 17.20 लाख करोड़ रुपये का अनुमान रखा गया था। इस तरह सरकार ने सालाना उधारी के लक्ष्य में 1,20,494 करोड़ रुपये यानी करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये की कटौती की है।

दूसरी छमाही में 7.86 लाख करोड़ रुपये की उधारी

वित्त मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही यानी अक्तूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच सरकार 7.86 लाख करोड़ रुपये बाजार से उधार लेगी। यह रकम सरकारी बॉन्ड जारी करके जुटाई जाएगी। इसमें 15,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा, दूसरी छमाही की पूरी उधारी 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये जुटाई जाएगी।

पहली छमाही में लक्ष्य से 13,500 करोड़ ज्यादा उधारी

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान सरकार करीब 8.13 लाख करोड़ रुपये की बाजार उधारी जुटाएगी। यह पहले तय 8 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से लगभग 13,500 करोड़ रुपये अधिक है। पहली और दूसरी छमाही की उधारी को मिलाकर पूरे वित्त वर्ष के लिए संशोधित बाजार उधारी 15,99,506 करोड़ रुपये बैठती है। एजेंसी

क्या होता है सरकारी बाजार उधार?

सरकार की आमदनी और खर्च के

बीच अंतर होने पर उसे अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार बाजार से पैसा उधार लेती है। इसके लिए वह सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियां जारी करती है। इन बॉन्ड को बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और दूसरे निवेशक खरीदते हैं। तय अवधि पूरी होने पर सरकार मूल रकम लौटाती है और ब्याज भी देती है।

ग्रीन बॉन्ड से क्या होगा?

दूसरी छमाही की उधारी में 15,000 करोड़ रुपये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे। इस रकम को सरकार पर्यावरण और हरित परियोजनाओं से जुड़े कामों में लगाने के लिए इस्तेमाल करती है। सरकार की पहली छमाही की उधारी योजना में भी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड शामिल थे। वित्त मंत्रालय ने मार्च में बताया था कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 8.20 लाख करोड़ की उधारी योजना में 15,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड शामिल थे।

ब्याज चुकाने में भी खर्च होता है उधारी का हिस्सा

सरकार की उधारी का एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने में भी जाता है। वित्त मंत्रालय के जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस अवधि में 4.27 लाख करोड़ रुपये ब्याज भुगतान पर खर्च किए थे। कुल सरकारी खर्च 17.62 लाख करोड़ रुपये रहा।

3 साल से 50 साल तक के बॉन्ड होंगे जारी

दूसरी छमाही में सरकार अलग-अलग अवधि के सरकारी बॉन्ड जारी करेगी। इनमें 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 और 50 साल की अवधि वाले बॉन्ड शामिल हैं। कुल उधारी में 10 साल की अवधि वाले बॉन्ड की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 26% होगी। इसके बाद 15 साल वाले बॉन्ड की हिस्सेदारी 17.6% और 5 साल के बॉन्ड की 12.1% होगी।

स्किल्स की कमी के कारण युवाओं को नहीं मिल पा रहा है रोजगार

क्या आपको डिग्री करने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिल पा रही है या जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन फेस करने पड़ रहे हैं या जॉब में नियमित ग्रोथ नहीं मिल पाती है, क्या आपने कभी इन सबके पीछे की वजह के बारे में सोचा है। इन सभी समस्याओं का कारण है 'डिजिटल स्किल्स' की कमी होना।

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार – भारत के कुल युवाओं में केवल 48.7 फीसद ही रोजगार योग्य हैं। इसका मतलब है कि हर 2 में से एक युवा रोजगार के योग्य नहीं हैं। व्ही–बॉक्स द्वारा जारी एक अध्ययन में कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल सभी कंपनियों में से लगभग 75 फीसद ने उद्योग में कौशल की कमी की सूचना दी है। जोकि अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण विषय है कई बार हम यह भी देखते हैं कि नॉन–कम्प्यूटर जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके निकलने वाले युवाओं को भी आसानी से नौकरी नहीं मिल पाती है। आज दुनियाभर में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। एक आंकड़े के मुताबिक, वर्तमान समय में दुनिया की एक बड़ी आबादी के करीब 6 बिलियन लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तब इन युवाओं को जॉब रेडी होने के लिए नए जमाने की स्किल्स सीखना जरूरी हो जाता है, जिसके बाद करिअर या व्यापार में आसानी से कम समय में अधिक ऊंचाई हासिल की जा सकती है।

इन 6 फील्ड में मिलेंगे लाखों जॉब्स के मौके अगर आप ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं या B.A, B.Sc, B.com, BC, सिविल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में अध्ययनरत हैं तो आपके पास डिजिटल स्किल्स सीखकर बड़े पैकेज वाली आकर्षक नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की मदद से अब तक अनेक युवाओं को लाखों के पैकेज वाली जॉब मिल चुकी है। ऐसे में आप भी इन फ़ील्ड्स में अपना शानदार करिअर बना सकते हैं –

- डिजिटल मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव
- सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट
- सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट
- क्रिएटिव कांटेंट राइटर/कॉपी राइटर
- PPC एक्सपर्ट
- गूगल Ads एक्सपर्ट

ये 5 स्किल सीखकर बनें डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट

एक शोध में सामने आया है कि आने वाले सालों में जिन क्षेत्रों में 85 फीसद नौकरियां क्रिएट होंगी वह डिजिटल मार्केटिंग, ग्रॉफिक्स डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डाटा साइंस जैसे क्षेत्र होंगे। अगर आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सफलता के एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की मदद से इस क्षेत्र में शानदार करिअर बना सकते हैं।

किसी उत्पाद या सेवा की डिजिटल टेक्नोलॉजी (इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, सर्च इंजन व अन्य चैनल) के जरिए होने वाली मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं।

डिजिटल मार्केटिंग का लक्ष्य एक असीमित ग्राहक संख्या तक कम समय में पहुंचना होता है। डेल कंपनी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर के साथ किए गए एक शोध में सामने आया है कि आने वाले सालों में जिन क्षेत्रों में 85 फीसद नौकरियां क्रिएट होंगी वह डिजिटल मार्केटिंग, ग्रॉफिक्स डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डाटा साइंस जैसे क्षेत्र होंगे। इसकी शुरूआत भी हो चुकी है बीते वर्ष डिजिटल मार्केटिंग विश्व की टॉप 5 नौकरियों में शामिल रहा है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि डिजिटल सेक्टर में करिअर बनाने जा रहे युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है। अगर आप भी अपना करिअर डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता केएडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की मदद ले सकते हैं।

इन 5 स्किल्स से बनें डिजिटल एक्सपर्ट

स्ट्रैटिजिक थिंकिंग – आजकल कंपनियों में स्ट्रैटिजिक थिंकर्स की काफी डिमांड है। अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ने पर बिजनेस ग्रो करने के लिए मार्केटिंग प्लान तैयार करने और उन्हें इम्प्लीमेंट करना जानते हैं तो डिजिटल सेक्टर में स्किल हासिल कर अपना करिअर बना सकते हैं।

डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स – डिजिटल सेक्टर में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक एडवरटाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई मेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग जैसे फील्ड्स में ढेरों नौकरी अवसर हैं। अगर आप डिजिटली स्किल्ड हैं तो डिजिटल सेक्टर में शानदार करिअर बना सकते हैं।

एनालिटिक्स – वहीं आजकल कंपनियों में बिजनेस एनालिसिस्ट की काफी डिमांड है। अगर आप एनालिटिकल टूल्स, गूगल एनालिटिक्स आदि को चलाना जानते हैं तो डिजिटल सेक्टर में करिअर बना सकते हैं।

कंटेंट क्रिएशन – आजकल लाखों वेबसाइट्स बेहतर कंटेंट को क्रिएट कर अपने उत्पाद, सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन आज के समय में मार्केटिंग सेक्टर में एक महत्वपूर्ण टूल है। इससे आप लक्षित ग्राहक संख्या तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

मार्केटिंग टूल्स एंड डिजाइन स्किल्स – मौजूदा समय में कंपनियों में मार्केटिंग टूल्स की समझ रखने वाले और डिजाइन स्किल्स जानने वालों के लिए भी बहुत मौके हैं। मार्केटिंग टूल्स जानने वाले मार्केटिंग प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। वहीं जो लोग एडोब, कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना जानते हैं वह डिजिटल सेक्टर में आकर्षक पैकेज पर जॉब हासिल कर सकते हैं।

कई सालों से अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिली है तो आप सफलता के डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज का हिस्सा बनकर डिजिटल सेक्टर में कम समय में आकर्षक पैकेज वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं।

ग्राफिक्स डिजाइनिंग में बनाएं भविष्य

इसके अलावा युवा ग्राफिक्स डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी करिअर बना सकते हैं। सफलता से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद कैंडिडेट्स के लिए वेबसाइट क्रिएटिव डिजाइन, एडवरटाइजिंग एजेंसी, पब्लिकेशन हाउस, कम्प्यूटर गेम्स, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जैसी कई अन्य जगहों पर आकर्षक वेतन वाली नौकरी के अवसर खुल जाते हैं।

लाखों के पैकेज के साथ शुरू हुआ करिअर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके पांच लाख का पैकेज हासिल करने वाले कार्तिकेय सिंह कहते हैं, 'मैंने कोर्स पूरा करने के बाद बतौर डिजिटल मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव के तौर पर नई पारी शुरू की है।'

इस कोर्स में क्या है खास

- 100 % प्लेसमेंट
- 100 घंटे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज
- 20 लर्निंग टूल्स
- 10 इंडस्ट्री बेस्ड मॉड्यूल्स
- 8 से अधिक लाइव प्रोजेक्ट और केस स्टडीज
- गूगल सर्टिफाइड एक्सपीरिएंस्ड फैकल्टीज
- साप्ताहिक डाउट क्लीयरिंग सेशन
- इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा मास्टर क्लास

सफलता के साथ बनाएं अपना करिअर

कई सालों से अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिली है तो आप सफलता के डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज का हिस्सा बनकर डिजिटल सेक्टर में कम समय में आकर्षक पैकेज वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं।

हर क्षेत्र में बेहतर भविष्य की राह अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र को एक ऐसे विषय के तौर पर देखा जा सकता है, जिसकी उपयोगिता लगभग हर क्षेत्र में होती है। सरल शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र समाज के सीमित संसाधनों का दक्षतापूर्ण ढंग से उपयोग करने की अनेक प्रणालियों का अध्ययन है। इसी बुनियादी नियम पर हमारी व्यावसायिक व आर्थिक इकाइयों की गतिविधियां टिकी होती हैं। अर्थशास्त्री आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण और विभिन्न नीतिगत विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। साथ में इनके भावी प्रभाव पर पैनी नजर रखते हैं, ताकि विकास दर पर नियंत्रण रखा जा सके। अर्थशास्त्री इसी दृष्टिकोण से काम करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र एक छोटी कंपनी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था जैसा बहुआयामी भी हो सकता है।

अर्थशास्त्र में सफल पेशेवर बनने के लिए आपमें उपलब्ध डाटा का विश्लेषण कर पाने की क्षमता का बेहतर होना जरूरी है। इसी क्रम में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की बुनियादी समझ बेहद जरूरी है। आर्थिक विषमताओं/स्थितियों को समझने–बूझने का निरीक्षण कौशल भी इसमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है।

अर्थशास्त्र 12वीं स्तर पर एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है,पर इस विषय में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अर्थशास्त्र से बीए (ऑनर्स) कोर्स से असली शिक्षा की शुरुआत होती है। हालांकि अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन के स्तर पर कई अन्य कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं। इनमें बीए(बिजनेस इकोनॉमिक्स), बीए(डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स) जैसे कोर्स का नाम लिया जा सकता है। देश के कई विश्वविद्यालयों में ये तमाम कोर्स कराये जाते हैं। अर्थशास्त्र से जुड़े विभिन्न कोर्सेज की मांग इसी बात से समझी जा सकती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में इसके ग्रेजुएट स्तर के कोर्स में प्रवेश पाने के लिए 90 फीसदी से अधिक अंक चाहिए होते हैं।

विशेषज्ञता की ओर बढ़ाएं कदम

ग्रेजुएशन में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मास्टर्स स्तर पर अर्थशास्त्र की कई शाखाओं में विशेषज्ञता अर्जित करने के लिए विकल्प दिए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से एनालिटिकल एंड एप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेशन एंड एप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इनके अलावा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स ,बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एन्वायर्नमेंटल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग इकोनॉमिक्स व रूरल इकोनॉमिक्स भी उल्लेखनीय हैं। छात्र चुनिंदा विश्वविद्यालयों में उपलब्ध एमबीए (बिजनेस इकोनॉमिक्स) कोर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। अर्थशास्त्र में पीजी डिप्लोमा और पीएचडी की राह भी चुन सकते हैं। देश के ज्यादातर सरकारी विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र से जुड़े कोर्सेज उपलब्ध हैं।

इंडियन इकोनॉमिक सर्विस

कम ही लोग जानते होंगे कि देश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरह इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी है। इसमें उपयुक्त प्रत्याशियों के चयन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करती है। इस परीक्षा में अर्थशास्त्र/स्टैटिस्टिक्स विषय में कम से कम मास्टर्स डिग्रीधारक युवा ही शामिल हो सकते हैं। प्रत्याशी की आयु 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक होनी चाहिए। इस परीक्षा में लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू लिया जाता है। लिखित परीक्षा में जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज व अर्थशास्त्र पर आधारित अन्य पेपर्स होते हैं। यह केंद्र सरकार की ग्रुप 'ए' सर्विस है। सफल प्रत्याशियों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद इनकी पहली नियुक्ति सहायक निदेशक के पद पर होती है। कार्यानुभव बढ़ने के साथ पदोन्नति पाते हुए प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के पद तक पहुंच सकते हैं।

विदेश में नौकरी के अवसर

अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों को विदेशी संस्थानों जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अलावा मल्टी नेशनल कंपनियों में शानदार मौके मिलते हैं। इनकी नियुक्तियां अर्थशास्त्री, नीति–निर्माता, एनालिस्ट, कंसल्टेंट आदि रूपों में होती हैं। विदेशों के सरकारी संस्थानों में भी भारतीय आर्थिक विशेषज्ञों की अच्छी–खासी मांग है। विदेश में बतौर रिसर्च स्कॉलर/प्राध्यापक के पदों पर आकर्षक पैकेज पर नियुक्तियां होती हैं।.

इस विशिष्ट कोर्स का उठाएं लाभ

देश के कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन स्तर पर तीन वर्षीय बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कोर्स उपलब्ध है। प्राय: परीक्षा के जरिये इस कोर्स की सीमित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा में वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से जुड़े ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के दस कॉलेजों में यह विशिष्ट कोर्स कराया जाता है। इनमें लगभग 480 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है।.

रोजगार के अवसर

निजी क्षेत्र की तमाम औद्योगिक इकाइयों, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्स, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्चुरियल साइंस आदि में इस क्षेत्र के पेशेवरों की मांग बनी रहती है। हर साल सरकारी क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नेशनल सैम्पल सर्वे तथा विभिन्न राज्य सरकारों के संबंधित विभागों आदि में बड़ी संख्या में अर्थशास्त्रियों की नियुक्तियां की जाती है। अर्थशास्त्र का शिक्षक भी बना जा सकता है।

चुनौतियां

- ग्रेजुएशन के बाद ही इस क्षेत्र में रोजगार के विकल्प बनते हैं। लेकिन ज्यादा अवसर उपलब्ध हो पाएं, उसके लिए उच्च अध्ययन की ओर कदम बढ़ाना जरूरी होता है।
- चूंकि इस क्षेत्र में आर्थिक विश्लेषण के लिए स्टैटिस्टिक्स, कैल्कुलस और ऊंचे दर्जे की गणित का इस्तेमाल होता है, इसलिए छात्रों को अनिवार्य रूप से गणित विषय पसंद होना चाहिए।
- अर्थशास्त्र की पढ़ाई को गंभीरता से लें। बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र के सिलेबस को काफी कठिन माना जाता है।

प्रमुख संस्थान

- दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली
- जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, मुंबई
- बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
- प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता

इंडियन नेवी का हिस्सा नहीं है मर्चेंट नेवी

अगर आपको समुद्र की लहरें अपनी ओर खींचती हैं और आपको घूमना–फिरना भी काफी पसंद है तो आप अपने इस शौक से जुड़ा ही कॅरियर विकल्प चुन सकते हैं और वह है मर्चेंट नेवी। अक्सर लोग मर्चेंट नेवी को इंडियन नेवी का हिस्सा समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह उससे बिल्कुल अलग है। यह एक कमर्शियल फील्ड है, जिसमें समुद्री जहाजों के जरिये एक जगह से दूसरी जगह सामान और यात्री को लाया ले जाया जाता है। चूंकि यह कार्य बड़े समुद्री जहाज के जरिए किया जाता है और उसके लिए प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है इसलिए मर्चेंट नेवी में कॅरियर के भी कई विकल्प मौजूद हैं–

क्या होता है काम

मर्चेंट नेवी में व्यक्ति अपनी योग्यता व स्किल्स के आधार पर अलग–अलग पदों पर काम करता है। आप वहां पर समंदर के नक्शों से लेकर इलेक्टानिक सामान की देखभाल, शिप का संचालन व यात्रियों को अन्य प्रकार की सेवाएं आदि प्रदान कर सकते हैं।

स्किल्स

चूंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें आपको घर से कई–कई दिनों तक दूर रहना पड़ता है, इसलिए मेंटली रूप से आपका इसके लिए तैयार होना जरूरी है। साथ ही आपको अपने काम के प्रति प्यार होना चाहिए, तभी आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। मर्चेंट नेवी में लोगों को टीमवर्क में काम करना होता है, इसलिए आपके अंदर यह गुण होना भी बेहद जरूरी है। वहीं इस क्षेत्र में आपको कभी भी जोखिम भरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना होता है।

योग्यता

इस क्षेत्र में अलग–अलग पोस्ट के लिए अलग–अलग योग्यता की जरूरत होती है। इस फिल्ड में 10वीं पास से लेकर बीटेक डिग्री वाले लोग अपना करियर देख सकते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में समय सीमा निर्धारित है। इस फिल्ड में जाने के लिए आपकी उम्र सीमा 16 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोर्स करके मर्चेंट नेवी में कॅरियर बना सकते हैं। जैसे 10वीं पास वाले व्यक्ति मर्चेंट नेवी में डिप्लोमा कर सकते है। वहीं अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास की है तो आप नॉटिकल साइंस, मरीन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट मेकेनिकल इंजीनिर्यस का कोर्स कर सकते है। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत अंक व आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

संभावनाएं

मर्चेंट नेवी में प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आप काम की संभावनाएं कई जगहों पर व कई पदों तक काम की तलाश कर सकते हैं। आप मालवाहक जहाजों से लेकर कंटेनर जहाजों, टैंकरों, थोक वाहक, और यात्री जहाजों आदि में बतौर रेडियो ऑफिसर, इलेक्टिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, नॉटिकल सर्वेयर व कप्तान के रूप में काम कर सकते हैं। चूंकि इस क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियां काम करती हैं तो आप सरकारी संस्थान में भी नौकरी के अवसर तलाश सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में आमदनी आपके पद व अनुभव के आधार पर तय होती है। इस क्षेत्र में शुरूआती सैलरी पद के हिसाब से 15000 से शुरू होकर 50000 तक जाती है। वहीं अनुभव व पद बढ़ने के साथ–साथ आप लाखों में कमा सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

- समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम, मुंबई
- मेरीटाइम फाउंडेशन, चेन्नई
- ट्रेनिंग शिप चाणक्य, मुंबई
- इंस्टीट्यूट ऑफ मरीनटाइम स्टडी, गोवा
- हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ नॉटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, उत्तरप्रदेश
- इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मरीन इंजीनियरिंग, कोलकाता
- तोलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट, दिल्ली
- महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पुणे
- इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई
- कोयम्बटूर मरीन सेंटर, कोयम्बटूर

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।